हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च, 1977

(पहली बैठक)

खंड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 24 मार्च, 1977

पृश्ठ

संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(2)1
अतारांकित प्र न एवं उतर	(2)45
सदन के मेज पर रखे गए। पुनः रखे गए कागज पत्र	(2)60
वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) का पे ा करना	(2)62
प्राक्कलन समिति का वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पर प्रतिवेदन पे ा करना	(2)62
वर्श 1971–72 तथा 1972–73 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों का पे ा करना	(2)62
नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव	(2)63
वर्श 1977–78 का बजट पे ा करना	(2)63

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 24 मार्च, 1977

(पहली बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़, में 9.30 बजे प्रातः हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

Lining of Fatehabad Branch in Hissar District

***1735. Ch. Mehar Chand:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any provision has been made in the current year's Budget for the lining of Fatehabad Branch in Hissar District; if so, the time by which the said work is likely to be takne in hadn and completed?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): No, Sir. The Project is still under investigation.

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने उतर में 'नो' कह दिया है हालांकि गर्वनर ऐड्रैस में और

बजट स्पीच में भी इसका जिकर है कि यह चैनल ऐप्रूवड है तो फिर इनका जवाब 'नो' में आया है, इसकी कोई समझ नहीं पड़ी।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, चौधरी मेहरचन्द जी की यह बात ठीक है, चैनल ऐप्रूवड है, बनेगी। मैंने अपने जवाब में कहा है कि परियोजना पर अभी जांच की जा रही है। हमने यह प्रोप्रोजल गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास भेजी हुई है, उनसे ऐप्रूवल आने पर कार्यवाही की जा सकती है।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चैनल का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

Sardar Harmohinder Singh Chatha: As early as possible.

Allotment of Free Plots to Harijans

***1737. Sh. Behari Lal Balmiki:** Will the Minister for Local Government be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to allot free plots to Harijans living in Faridabad Complex; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the time by which the proposal is likely to be implemented?

State Minister for Development and Local Government (Ch. Gordhan Dass Chuahan):

(a) Yes, there has been a proposal to allot free plots to Harijans and landless labourers living in villages forming par of the Faridabad Complex.

(b) The Scheme has been implemented by alloting plots to persons found eligible.

चौधरी मेहर चन्द: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का कश्ट करेंगे कि किन–किन गांवों में कितने–कितने प्लाट्स लोगों को दिये गये हैं ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहान: अध्यक्ष महोदय, हमने ऐप्लीके ानज मांगी थी। कुल 562 एप्लीके ानज आई थी उनमें से 225 को प्लाट्स दे दिये गये और जो बाकी 337 रह गये थे उनको भी प्लाटस दिये गये हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कब्जा नहीं लिया है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन 225 लोगों को प्लाट्स दिये गये हैं क्या इन प्लाट्स की रजिस्ट्री उनके नाम हो गई है ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहान: जी हां, वह हो रही है ?

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि जैसे इन्होंने हरिजनों को प्लाट्स दिये

हैं क्या उसी प्रकार बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को भी प्लाट्स देने की सरकार की कोई स्कीम है ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, अगर उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो हम इस बात पर भी विचार कर लेंगे।

श्री बिहारी लाल वाल्मीकिः क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि फरीदाबाद कम्पलैक्स बल्लभगढ़ और न्यू टाऊनि ाप में किन–किन हरिजनों को प्लाट्स दिये गये हैं ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, यह स्कीम अभी विलेजिज में थी, अरबन एरियाज में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अगर ऐसी कोई स्कीम सरकार ने बनाई तो फिर हम ऐसे केसिज कंसिडर कर लेंगे।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जिन लोगों को प्लाट्स दिय गये हैं, क्या सरकार उन प्लाट्स पर उन को मकान बना कर देगी या कोई लोन देने की सरकार की स्कीम है जिससे वे लोग मकान वगैरह बना सकें ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, इस वक्त हम 25 हजार के करीब मकान बना रहे हैं और उन में कुछ विलेजिज छांट लेंगे और लोन से मकान बनाकर देंगे।

श्री के.एन. गुलाटीः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद में जिन हरिजनों के पास चौपालों के लिए प्लाट्स नहीं है उनको चौपालों के लिए प्लाट्स दिये जाऐंगे ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, जिन–जिन गांवों में चौपालों के लिए जगह नहीं है उनको इसके लिए एड वगैरह भी दी जाएगी।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो हरिजन या बैकवर्ड जाति के लोग किसी जगह पर प्लाट्स वगैरह से वंचित रह गये हैं और जो सरकार के उस क्राइटेरिया में आते हैं उनको भी अब कंसिडर किया जाएगा ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, यह तो फरीदाबाद कम्पलैक्स का सवाल है, वैसे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो मोस्ट एलिजीबल आदमी है उनको भी कंसिडर करेंगे।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद कम्पलैक्स या दूसरे भाहरों में जो प्लाट्स सरकार देगी वह फ्री आफ कास्ट होंगे या कि उनकी कीमत ली जाएगी ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, मैंने भाहरों के बारे में नहीं कहा, मैंने यह कहा है कि जो गांव फरीदाबाद कम्पलैक्स में आते हैं उनको प्लाट्स दिये जाएंगे।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिस प्रकार गांवों में प्लाट्स दिये गये हैं क्या सरकार की अरबन एरियाज में उसी प्रकार प्लाट्स देने की कोई स्कीम है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत देहातों में उन लोगों को जो बैकवर्ड क्लासिज के हैं या हरिजन हैं और जिनके पास कोई रिहाय ी मकान नहीं है, रिहाय ा के लिए प्लाट्स देने का प्रस्ताव था और जितने ऐलिजिबल थे, कुछ को छोड़कर गिनती अभी मेरे पास नहीं है, हमने सबको प्लाट्स दे दिये हैं। 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत अरबन एरियाज में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं था फिर भी हरियाणा सरकार ने यह नि चय किया है कि म्युनिसिपल कमेटी या इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के द्वारा प्रबन्ध किया जाये कि नो–प्रोफिट नो–लोस के बेसिज पर जो अरबन एरियाज दिये जाएं। कई जगहों पर तो प्लाट्स दे दिये हैं और जो ऐलिजीबल हैं उनको प्लाट्स दिये जाएं। कई जगहों पर तो प्लाट्स दे दिये हैं और जिन जगहों पर प्लाट्स नहीं दिये गये हैं वहां पर दिये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो 225 प्लाट्स दिये गये हैं यह कितने–कितने एरियाज के हैं और किस कीमत पर दिये गये हैं ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः फ्री आफ कास्ट दिये गये हैं और 100 मुरब्बा गज के हैं।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, अभी–अभी मुख्य मंत्री ने जो 20 सूत्री प्रोग्राम के बारे में कहा है इसमें जो फैमिली प्लानिंग के प्वायंट हैं, क्या उसको भी खत्म किया जाएगा ? .... (ाोर)

Mr. Speaker: Order please. It is not a supplementary.

श्री बनारसी दास गुप्ताः वह भी समय आने पर बता देंगे।

लाला रूलिया रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो प्लाट्स दिये गये हैं यह कागजों पर ही हैं या कि इनका कब्जा भी दे दिया गया है ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः कब्जे भी दिलवा दिये हैं और रजिस्ट्रे ान भी हो चुकी है।

मलिक सतराम दास बतराः स्पीकर साहब, कई जगहों पर नोटीफाइड एरिया कमेटी बन गई हैं वहां पर कुछ जमीन

सरप्लस पड़ी हुई है क्या सरकार वह जमीन गरीब हरिजनों को चौपालों के लिए देने के लिए तैयार है, अगर तैयार है तो फ्री दी जाएगी, या कि उसकी कीमत ली जाएगी ?

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के पास गांवों में चौपालों के लिये जगह नहीं है उनको चौपालें बनाने के लिए प्लाट देने पर सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, चौपालों के लिए भी प्लाट्स दिये जाएंगे।

श्री बिहारी लाल वाल्मीकि: अध्यक्ष महोदय, न्यू टाऊनशिप फरीदाबाद में हरिजनों के लिए चौपालें नहीं है, खुशी और गर्मी में बैठने के लिए उन लोगों के पास कोई जगह नहीं हैं क्या ऐसे लोगों को चौपालों के लिए प्लाट्स देने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहान: फरीदाबाद टाऊनशिप में हरिजनों की आबादी कितनी हैं और कितने परसेन्ट लोगों को प्लाट्स अलाट किये गये हैं ?

चौधरी गोवर्द्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, आबादी की बात नहीं है, हमने एलिजीबल आदमियों को कंसिडर करके अलाटमैंट की है।

B.K. Hospital Faridabad

***1741. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the total number of beds at present in B.K. Hospital Faridabad including T.B. Ward;

(b) the strength of class-I, class-II, class-III & class-VI employees in the hospital as referred to in part(a) above; and

(c) whether the strength of employees in the hospital referred to in part(a) above is proportionate to the bed-strength; if not, the time by which the strength of employees is likely to be increased?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमति भारदा रानी):

(क) 200 बिस्तर।

(ख) बी.के. हस्पताल, फरीदाबाद में श्रणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4

2	11	82	52

(ग) 200 बिस्तर के हस्पतालों के लिए अनुमोदित स्टाफिंग नार्म के अनुसार बी.के. हस्पताल फरीदाबाद में श्रेणी 1, श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 कर्मचारियों की संख्या उसमें बिस्तरों की संख्या के अनुपाती है। श्रेणी 4 कर्मचारियों की संख्या में कमी हैं। इसे वर्श 1977–78 में पूरी कर दी जाने की संभावना हैं।

Construction of Roads

***1744. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Revnue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads up to 31-3-77 & 31-3-78 in Bawani Khera constituency in Bhiwani District:-

(a) Pur to Siwara.

(b) Siwani to Bawani Khera.

(c) Rathera to Tosham.

(d) Jamalpur to bawani Khera.

(e) Rohnat to Bawani Khera, and

(f) Bawani Khera Bye-pass.

राजस्व मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): प्रत्येक सड़क की स्थिति को द ार्ाता हुआ एक विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

Statement

(a) Pur to Siwara.- Govt have approved the construction of this roads. However no date has been fixed for its completion, which depands upon the availability of funds and acquisition of land.

(b) Siwani to Bawani Khera.- Govt have approved the construction of this road up to Balawas only, from Siwani. However no date has been fixed for its completion, which depands upon the availability of funds.

(c) Rathera to Tosham.-It has been decided that the case regarding constuction of this road should be kept pending till the financial position eases.

(d) Jamalpur to bawani Khera.

(e) Rohnat to Bawani Khera, and- It has been decided that the case regarding constuction of this road should be kept pending for the present.

(f) Bawani Khera Bye-pass.-Govt have approved the construction of this bye-pass, however, no date has been fixed for its completion, which depands upon the availability of funds.

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि स्टेटमेंट मे नम्बर एक पर जो सड़क दिखाई गई है उसका कितना काम बाकी है और वह कब तक मुकम्मल हो जाएगी ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसकी मंजूरी 12 जनवरी, 1977 को हो चुकी है और यह काम जल्दी खत्म हो जाएगा।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिस जगह पर कोई लिंक रोड नहीं है, वहां पर बनाने का विचार है ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसका जवाब पिछले सै ान मेंदिया जा चुका है। उस समय बताया गया था कि हमने तीन कैटेगरीज बनाई हुई हैं उनके हिसाब से ही काम करेंगे जैसे जहां बीच में गैप पड़े हैं उनको पहले करेंगे। ऐसे गैप्स को अगले साल के अन्त तक तैयार कर दैंगे।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): मंत्री महोदय ने कैटेगरीज का जिकर किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि कई जगह कोई लिंक ही नहीं हैं तो वह सड़कें किस कैटेगरी में आती है क्या उसको भी जल्दी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री माडू सिंह मलिकः जहां कोई सड़क नहीं है वह बी कैटेगरी में आती है।

चौधरी पीर चन्दः नंबर एक पर दी गई सड़क के बारे में मंत्री महोदय ने अभी बताया कि इसको जल्दी खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जल्दी कब तक कर देंगे एक महीने में या दो महीने में ?

श्री माडू सिंह मलिकः जवाब में लिखा गया है कि जैसे ही पैसे अवेलेबर होंगे हम यह काम कर देंगे।

श्री अमर सिहः मंत्री महोदय ने स्टेटमैंट में दी गई 'बी' सड़क के बारे में बताया है कि यह सड़क सिवानी से बालावास तक ही बनेगी। मेरा निवेदन यह है कि सिवानी से बवानी खेड़ा कोई ज्यादा लम्बा रूट नहीं है इसलिये यह सारी सड़क ही बना देनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि सिवानी से बालावास तक का जो टुकड़ा है वह कब तक मुकम्मल हो जाएगा ?

श्री माडू सिंह मलिकः यह एक तरह से डबल लिंक है क्योंकि यह गांव पहले तहसील हांसी में थे अब भिावनी में आ गए है। यह 24 किलोमीटर लम्बा रूट है और इस पर 24 लाख के लगभग खर्च होंगे। जैसे ही पैसे मिलेंगे हम इस काम को कर देंगे।

श्री गौरी भांकरः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कलायत से दातासिंहवाला सड़क कब तक बन जाएगी ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसके लिये सैपरेट नेाटिस चाहिये।

श्री हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, अगर महम से जुलाना तक जोकि बीच में चार किलोमीटर का टुकडत्रा है बना दिया जाए

तो यह लौंग रूट बना जाएगा क्या मंत्री महोदय इसे बनाने का विचार रखते है ?

श्री माडू सिंह मलिकः इस पर इस समय कोई विचार नहीं किया जा सकता।

श्री के.एन. गुलाटीः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाली और गुडगांव के दरम्यान थोड़ा सा टुकड़ा बाकी है अगर उसको बना दिया जाए तो फरीदाबाद का रास्ता छोटा पड़ता है। क्या इसको बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री माडू सिंह मलिकः यह पाली या गुड़गांव का सवाल नहीं है इसके लिए अलग से नोटिस चाहियें।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जमालपुर से बवानी खेड़ा और रोहनात से बवानी खेड़ा सड़क का केस कब तक पैंडिग रखा जाएगा और इसके बारे में कब तक फाइनल डिसीजन होगा ?

श्री माडू सिंह मलिकः यह डबल लिंक है और इस कैटेगिरी का जब नंबर आएगा तो उस वक्त इस पर विचार किया जाएगा।

श्री हरस्वरूप बूराः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सरकार का महम में कोई बाई पास बनाने का विचार है ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिये।

श्री हरि सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने या दूसरे मिनिस्टर साहिबान ने जो पब्लिक मीटिंग्ज के अन्दर सड़कें बनाने का एलान किया था उनके बारे में सरकार की पालिसी क्या है ? पब्लिक फेथ हासिल के लिए इन सड़कों को कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री माडू सिंह मलिकः रोड्ज के बारे मे जो एलान मुख्य मंत्री जी की ओर से यिका गया है उनको जरूर पूरा किया जाएगा।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हिसार बाई पास कब तक कम्पलीट कर दिया जाएगा ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिये।

Providing Employment

***1746. Ch. Ram Lal wadhwa:**Will the Chief Minister be pleased to refer to unstarred question No. 386 replied on 13th Januray, 1976 and to state the steps taken by the Government to provide Employment to unemployed persons so far in the State and results thereof?

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass GuptaThe State Government has been implementing various special

Emloyment Programmes from time to time for providing jobs to unemployed persons.(i) Crash Scheme for Rural Employment, (ii) Special Emlpoyment Progarmme-Road Construction, (iii) Programme for Educated une employed, (iv) Half A Million Jobs programme and (v) Employment Promotion Programme, have been implemented (vi) Sufficent employment has been created in Government Departments through the implementation of Plan and Non-Plan Schemes.

In addition, a large number of educated persons are being trained under the Apprenticeship Act and in the Community Projects Centres and Rural Industrial Development Centres of the Industries Department thereby enhancing their employability Prospects.

Details of employment opportunities under these entire programme schemes are placed on the Table of the House.

Empolyment Provided/potenial created for un-employed persons in Haryana 1973-74 to 1976-77

Sr.	Progarmme/Scheme	Employment Provided/potenial created (No. of persons)			
		1973-74	1974-75	1975-76	1976-77 (Potential)
1	2	3	4	5	6
I.	Central Sector				

	Programme- 1. Crash Scheme for Rural Employment, 2. Special Emlpoyment Progarmme-Road Construction. 3. Programme for Educated une employed. 4. Half A Million Jobs programme. 5. Employment Promotion Programme.	5357 1253 1948 281	280 49	380 361	650 1151
II.	State Sector Scheme-				
1	Loans aranged from Commercial Banks/financial Institution for persons belonging to weaker section for purchase of rickshaws, scooters			1530	5744

	and seting up petty occupation (Employment Department)				
2	Seed Capital/margin money assistance to educated unemployed persons for seeting up self employment units (industries Department).			155	340
3	Subsidy/Laons granted tp persons belonging to scheduled Castes/Backward Classes categories for purchase of pigs and polutrry birds (Social Welfare Department)	320	349	492	225
4	Appointments of Indiviual in the undertaking run by the Nigam and Loans advanced to scheduled	371	617	398	442

	Castes/Backward Classes persons for self employment units (Haryana harijan Kalyan Nigam)				
5	Grants/Loand advanced to indiviuals/Coop-Socitioes for setting up various units such as pottery, blacksmithy, soap making etc. in Khadi & Village Industies Sector (Khadi & Village Industies Board)	102	1687	1648	3104
6	No. of persons directly employed by the Govt.	12399	9905	N.A.	N.A.
Toatl		22031	12887	4064	11656

Sr.	Progarmme/Scheme	Employment Provided/potenial created (No. of persons)			
		1973-74	1974-75	1975-76	1976-77 (Potential)
1	2	3	4	5	6
I.	Persond Trained				
1.	No. of persons who remained under training under the Apprenticeship Training	655	805	3810	4510
2.	No. of persons trained in Community projects centres and Ruarl Industries Development Centres run by the Industries Development.			222	149
Total		655	805	4032	4659

*Includes both Casual and regular workers. In respect of Casual Workers, employment during the year has

been arrived at on the basis of full employment for each worker during the year.

@ Actual Up to 28-2-1977.

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करैंगे कि यह जो स्टेटमैंट मुझे दी गई है इसमें जनरल सैक्टर प्रोग्राम के तहत 1973–74, 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में एम्पलायमैंट/ पोटैंि ायल के बारे में फिग्गर्ज दी गई हैं जोकि बहुत ही कम हैं जबकि इस समय आपका बसी सूत्री प्रोग्राम भी चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि एम्पलायमैंट का पूरा प्रबन्ध न होने की क्या वजह है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, देहात में रोजगार देने के लिए जो यह क्रै ा प्रोग्राम चलाया गया यह भारत सरकार की ओर से था। केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए हमें सहायता दी थी और यह सहायता हमें अक्तूबर, 1974 तक मिलती रही और तब तक यह प्रोग्राम रहा।

चौधरी ि िाव राम वर्माः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे जैसे कि उन्होंने कई प्रोग्राम गिने हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों नौकरी देने के लिए 5–5 नसबन्दी और नलबन्दी के केसों की भार्ते रखी गई वह कौन से प्रोग्राम में आता हैं ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः ऐसी कोई भार्त नहीं लगाई गई थी।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि 'अपने–रोजगार' के तहत सरकार ने कितना कर्जा बैंको से लोगों को दिलवाया और कितने लोगों को रोजगार मिला।

श्री बनारसी दास गुप्ताः कितने लोगों को रोजगार मिला यह सारा विवरण जवाब मैं दिया हुआ है सम्मानित सदस्य उस विवरण को देख सकते हैं और जहां तक रकम दिलवाने का सवाल है वह फिग्गर इस समय मेरे पास नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि सैन्ट्रल ऐड खत्म होने के बाद हरियाणा सरकार ने अपने तौर पर क्या कोई कदम सोचा है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हमने अनेक प्रकार के कदम बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए उठाए है जैसे देहात में लोगों को काम देने के लिए सड़क निर्माण का काम आज तक भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमने एक और कदम उठाया है। हमने स्टेट में एक लेबर कंस्ट्रक ान कोआप्रेटिव बोर्ड बनाया है और हमारा यह नि चय है कि उसकी भााखाएं प्रत्येक ब्लाक में खोलें और हम यह चाहते हैं कि जितने भी काम करवाए जाते हैं उनमें ठेकेदार को एलीमीनेट किया जाए और काम सीधे लेबर कंस्ट्रक ान कोआप्रेटिव सोसाइटी को दिया जाए ताकि देहात में रहने वालों को काम मिल सके। इसके अलावा हमने यह कदम भी उठाया है कि जो भाई देहात में रहने वालों को काम

मिल सके। इसके अलावा हमने यह कदम भी उठाया है कि जो भाई देहात में बसते हैं, रूरल आर्टिजंज उनके लिए हनमे एक कार्पेरे ान बनाई है जिसका नाम है हैंडलूम एंड हैंडी क्राफट कार्पोरे ान। इसके द्वारा हम सब रूरल आर्टिजंज को पैसा भी देंगे, कच्चा माल भी देंगे और उनके तैयार माल को बेचने का भी प्रबन्ध करेंगे। इस प्रकार के अनेक प्रोग्राम हरियाणा सरकार की ओर से चलाए गए हैं।

चौधरी रिजक रामः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसी जांच पड़ताल की है कि स्टेट में कितने आदमी अन–एम्पलायड हैं, कितने अंडर एम्पलायड है और कितने सैमी एम्पलायड हैं ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः इस प्रकार का सर्वे हमने करवाया है अगर सम्मानित सदस्य अलग से नोटिस दें तो सारी सूचना दी जा सकती हैं।

चौधरी पीर चन्दः मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जब तक सैन्ट्रल गवर्नमैंट ग्रान्ट देती रही तब तक वे काम चलाते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या भारत सरकार ने ग्रांट देने से इन्कार कर दिया था ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इसका यह मतलब नहीं है कि वह ग्रांट बन्द होने के बाद एम्पलायमेंट देने का काम बन्द हो गया है। वह क्रै ा स्कीम जो केन्द्रीय सरकार की

तरफ से थी, बन्द हो गयी और हमारे मांगने पर दी गई या देने से इन्कार कर दिया हो, इस बात का मुझे मालूम नहीं।

श्रीमति लेखवती जैनः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि वह कितनी रकत हैं जो गांवों में भैसें, मुर्गियां और सूअर पालने के लिए कर्जे के रूप में दी गई है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसे कर्जे, भैंसे पालने के लिए, मुर्गियां पालने के लिए, सूअर पालने के लिए और दूसरे अनेक धन्धों के लिए दिलवाए हैं, लेकिन कितनी रकम इन धंधों के लिए कर्जे के रूप में या ग्रांट के रूप में दी गई हैं, इसकी फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि क्या उन्होंने स्टेट में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि अगले साल इतने लोगों को रोजगार दे दिया जायेगा ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि रोजगार देने के लिए हमने अनेक प्रकार के कदम उठाए हैं और हमारा इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाए।

लाला रूलिया रामः जैसा कि चौधरी ि ाव राम वर्मा ने कहा था कि जिन लोगों ने फैमिली प्लानिंग के पांच–पांच केस दिए हैं उनको सरकार नौकरियां देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिन्होंने पांच–पांच केस दिये हैं उनको नौकरियां नहीं दी और

अगर दी भी है तो बाद में हटा दिया गया है। क्या मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है, अगर मेम्बर साहब के नोटिस में ऐसी कोई बात है तो मुझे बताएं।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, सरकार ने डिफैट क्रै ा प्रोग्राम, अन–एम्पलायमेंट को दूर करने के लिए स्टेट में भाुरू किए हैं, चाहे वे सैन्ट्रल गवर्नमैंट की मदद से किए हैं चाहे खुद किए हैं। क्या इन प्रोग्राम्ज के बावजूद स्टेट में अन–एम्पलायमैंट घटी है या बढ़ी है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः जितने लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराए हैं उसकी सारी फिगर इस सवाल के जवाब में दी गई है।

राव बंसी लालः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लेबर कंस्ट्रक ान कोआप्रेटिव सोसायटी बोर्ड के द्वारा लोगों को वर्क दिया जाता है ठेकेदारों के मुकाबले में और ठेकेदारों से अरनैस्ट मनी लिया जाता है। क्या मंत्री महोदय लेबर कंस्ट्रक ान कोआप्रेटिव सोसायटी बोर्ड से, ठेकेदारों के मुकाबले में, यह अरनैस्ट मनी की भार्त रिमूव करेंगी ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अरनैस्ट मनी नहीं ली जाती बल्कि ठेकेदारों के मुकाबले में और भी सुविधाएं ऐसी सोसाइटीज को दी गई हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या यह ठीक है कि एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज में 6 लाख के करीब बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं और पिछले सालों में 10 हजार लोगों को भी सरकार एम्पलायमैंट नहीं दिला सकी ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जितने लोगों को हमने रोजगार दिलवाया है उन सब का ऐम्पलायमैंट एक्सचेंजिज में नाम रजिस्ट्रर करवाना कोई जरूरी नहीं है। जो फिगर इनके पास हैं, मुझे पता नहीं ठीक है या गलत, लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कितनों को रोजगार मिला है, इसके लिए यदि यह अलग से नोटिस दें तो सूचना दी जा सकती है।

चौधरी रिजक रामः मुख्य मंत्री जी ने फरमाया है कि लेबर कस्ट्रक ान कोआप्रेटिव सोसायटी बोर्ड के जरिए लौगों को रोजगार देने की योजना बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बोर्ड में ज्यादातर सोसायटियां ठेकेदारों की है और मजदूरों को पहले की तरह ही ठेकेदारों के द्वारा एक्सप्लायट किया जा रहा है। क्या मुख्य मंत्री महोदय इसके बारे में इन्क्वायरी करवायेंगे और

ठेकेदारों की बजाय मजूदरों की सोसायटियां बनाने की कोि ा ा करेंगे ?

Mr. Speaker: Order please. This is not a supplementary.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि करनाल भाूगर मिल में जिन लोगों को नौकरियां मिली है, क्या वह नौकरियां बिना भार्त से मिली हैं या इस भार्त पर मिली है कि जो पांच पांच केस फैमिली प्लानिंगे के लाएगा उसको ही नौकरी दी है ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: यह बात गलत है, निराधार है, गलत प्रचार है और यही गलत प्रचार करके, इन्होंने लोगों को भरमाया है (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: आप इसकी इन्क्वायरी करवा लें, अगर गलत हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी का एलान कर दें ? (व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please. Next question.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: आप इन्क्वायरी करवाएं लोगों ने अढ़ाई–अढ़ाई हजार रूपये खर्च किए हैं (व्यवधान) लोग मारे मारे फिरते रहे।

Mr. Speaker: Order please. Next question.

Cottage Industries

***1736. Ch. Mehar Chand**: Will the minister for Industries be pleased to State-

(a) the names of the villages where cottage Industries have been statred in the State, particularly in Hissar District;

(b) the kind of Industries as referred to in part (a) above introduced at each place; and

(c) Whether the articles manufactured by the Industries as referred to in aprt (a) above find ready sale?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh):

(a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) No difficulties in respect of sales have been brough to the notice of the Government.

Sr.	Name of District	Name of Village	Name of the cottage Industries.
1	2	3	4
1.	Hissar	Rampura	Handloom
		Majra	Handloom
		Kheri Jalah	Handloom
		Siswal	Shoe-making

		Sisai Kalirawan	Handloom
		Dhani	Handloom
		Lahari Ragnu	Handloom
		Madha	Handloom
		Bhaini Badshahpur	Shoe-making
		Umra	Shoe-making
		Narnaund	Shoe-making
		Jakhal	1. Candal 2. Pottery
		Nai Basti Jakhal	Pottery
		Puthi Samian	Shoe-making
		Jamaori	Shoe-making
		Nangal	Pottery
		Talwara	Pottery
		Ladwa	Shoe-making
		Bhatla	(i) Shoe-making (ii) Wooden Work
		Badopal	Shoe-making
		Dhani Pal	(i) Shoe-making

			(ii) Wooden Work
		Rakhi Shahpur	Shoe-making
		Budana	Agricultural Implements
		Brass	Ban & Rope Making
		Salimgarh	Candle Making
		Budha Khera	Wooden Work
		Barwala	Wooden Work
		Shekhpura	Wooden Work
		Sisai Khurbla	Wooden Work
		Bandha Heri	Wooden Work
		Dhani Brahmin	Wooden Work
		Ratia	Wooden Work
		Daultpur	Wooden Work
		ratia	Do
		Dem Kaura	Shoe making
		Malapur	Male Beeds
		Nangthala	Do
		Akbarpur	Handloom

		Mirapur	Do
2.	Sirsa	Jassania	Shoe Making Hosiery
		Mehrana	Handloom
		Jag Malera	Weaving
		Rania	Poultry
3.	Bhiwani	Dipot	1. Rosary Beeds .
		Biran	3. Agri. Implements ments
		Khank	4. Wooden Furniture.
		Jhoju Kalan	5. Stone Carving
		Badera	6. Handloom 7. Artistic Durrees 8. Pirhas 9.Murhas 10. Sirkies.
4.	Rohtak	Meham	1. Handloom 2. Shoe Maikn

			3. black smithy 4. Carpentry 5. Gur & Khandsari 6. Oil Crushing 7. Detergent Making 8. Pottery 9. Agr. Implements 10. Cotton Ginning
		Kalannaur	1. Handloom 2. Poultry Farming 3. Soap Making 4. Agri. Implements
		Madina	1. khandsari 2. Pottery
		Ladpurs	Poultry Farming
		Sanghi	Poultry Farming
		Kharak Kalan	1. Shoe Making 2. Soap Making
		Nandal	Duree Making

		Bhagotipur	Handloom
		Kaloi	Duree Making
		Farmana	Handloom
		Attali	Shoe Making
		Pakasma	Do
		Balyana	Agri. Implements
		Lakhanmajras	Shoe Making
		Chiri	1.Shoe Maikng 2. Pottery
		Khadwali	1. Shoe Making 2. Poultry farming 3. Pottery 4. Agri. Implements
		Samar Gopalpur	1. Poultry Farming 2. Pottery
		Titoli	Pottery
		Kharkara	Shoe Making
		Kheri meham	Shoe Making
		Nidana	1. Shoe Making

			2. Pottery
		Mungan	1. Carpentary 2. Blacksmithy
		Lahli	Polutry Farming
		Sampla	1. Oil Crushing 2. Soap Making 3. Detergent Making 4. Blacksmithy 5. Agri. Implements 6. Cotton Ginning
		Rewari Khera	Poultry Farming
		Beri	1. khandsari 2. Blacksmithy 3. Agri. Implements
		Dujana	Surgical Cotton Dressing
		Ismalia	1. Gur and Khandsari 2. Shoe Making
		Dnaur	Khandsari

		Suhra	Blacksmithy
		Chhuchhakwas	Agri Implements
		Isthal Bohar	Pharmacy
		Azad Nahar	1. Mudha Making 2. Shoe Making 3. Poultry Farming
		Bhakli	1. Mudha Making 2. Handloom
		Talao	Mudha Making
5.	Sonepat	Budh Khalsa	waste Rubber Grinding
		Rai	Forging
		Khar Khudas	Handloom
		Ganaur	Plastic Articles
		Mohana	Brick Kiln
		Khanda	Do
		Murthal	Washing Powder
		Chichrana	Shoes Desi
		Rajlu Garlu	Oil extraction

		Jatheri	Agri. Implements
		Karaw	Flour Mills
		Butana	Shoe making
		Garhwal	Do
		Gohana	1. Shoe Making 2. Tanning 3. Blacksmithy 4. Handicrafts 5. Bandage 6. Electric Motor 7. Agri. Implements
		Mehmoodpur	Carpentary
		Bali	1. Blacksmithy 2. Shoe making
		Kathura	1. Pottery 2. Shoe Making
		Barodas	Shoe Making
		Chilkana	1. Shoe Making 2. Weaving

		Chapia	Shoe Making
		Kami	Shoe Making
6.	Kurukshetra	Ratta Kheri	Handloom
		Gumthalagarhu	1. Handloom 2. Nisadar
		Siwan	Carpentry
		Babani	Do
		Pipli	Saw Milling
		Ismailabad	Fabrication Radio AssemblingMenthol
		Bershani	Menthol
		Kaul	1. Shoe making 2. Cement Jallie. 3. Dairy farming
		Dhand	Cement jalli
		Umri	shoe maiking
		Bori	Dairy farming
		Dera	Flour Milling
		Garhi	Carpet making

		Kotaha (Teh. Nariangarh)	Ban Making
		Ratangarh (Teh. Ambala)	Durreee Making
		Mehmoodpur (Teh. Nariangarh)	Ban Making
		Thane-Ki-Sair (Teh. Kalka)	Basket making
		Khas Mangoli (Teh. Kalka)	Do
		Toran (Tehsil Kalka)	Do
		Nolta (Do)	Do
		Kalka	Basket Making Candle making
		Panchkula (Teh. Kalka)	Basket Making
		Khol-Mola (Do)	Ban Making
		Khol Fateh Singh (Do)	Ban Making

		Nai Nagar (do)	Do
		Bitana Teh. Kalka)	(i) Ban Making (ii) Kundli Making
		Rampur jangi (Teh. Kalka)	(i) Ban Making (ii) Khess and Khaddar weaving
		Gorakh Nth (Teh. Kalka)	Ban Making
		Kiratpur (Teh. Kalka)	Ban Making
		Shahpur (Teh. Kalka)	Ban Making
		Karmpur (Teh. Kalka)	Ban Making
		Pinjore (Teh. Kalka)	1. Chalk Making 2. Paraffin wax Making 3. Candle Making
		Chhachrauli	Ban Making
		Midhapur (Teh.	Khess and Khaddar

		Kalka)	weaving
		Shadipur	Lime Kiln
		Sasuli	Do
		Chuneti	Do
		Mustafabad	Do
		Azizpur Kalan	Pottery
		Jagadhri	Do
		Bilaspur	Do
		Mutafabad	Do (i) Soap Making (ii) Alumininum Utensil Mfg.
		Buria	Alumininum Utensil Mfg.
		Kattarwali	Do
		Chhachrauli	Do
		Khadri	Do
		Raiwali	Do
		Rattangarh	Do
7.	Gurgaon	Mubarkpur-	Murha Making

		Jharsa- Sidhrawali-	Tilla Jutties 1. Stationery Goods 2. Candle Making 3. Chalk Making
		Dharuhera	1. Mudha making 2. Ban Making.
		Pali	Do
		Chandpura	Do
		Asiaki gorawas	1. Shoe making 2. Tanning
		Odhi	Do
		Qutabpur	1. Shoe making 2. Tanning
		Rampura	Do
		Malaudi	Do
		Harchnadpur	Do
		Dharu hera	Do
		Nandpur Bash	Do
		Bikaner	Do

		Attali	Do
		Bachod	Do
		Goad	Do
		Balahan Kalan	Shoe Making
		Balahan Khurd	Tanning
		Mohindergarh	Do
		Kurrawash	Do
		Dhanoda	Do
		Nangal Chudhary	Do
		Nangal Durgo	Do
		Dhani Bhatota	Do
		Sureli	Weaving
8.	Karnal	Smalkha	1. Agr. implements 2. Cane Crushing 3. Pulleys 4. Totas Handles 5. Purnala 6. Desi Jutties 7. Trollies

		Babarpur	Handloom (Khes and Chaddar)
		Babail	1. Comber cloth (export) 2. Desi Jutties.
		Khand	Absorbent Cotton
		Bapauli	Soap Washing
		Israna	1. Engg. workshop 2. Rice Sheller 3. Desi Jutties
		Madlauda	1. Rice sheller 2. Fabrication works
		Ugra Kheri	Hosiery
		Urlana Kalan	1. Saw Mill 2. Washing Soap
		Ahar	1. weaving 2. Desi Jutties 3. Atta Chakki 4. Oil Kohlu 5. Cotton Ginning

		Kurar	Atta
		Bhaddar	Leather Tanning
		Assandh	Weaving, Knit wears, Shoe making, socks making
		Indri	Do
		Nissang	do
		Gharaunda	do
		Kaund	do
		Bal Ranharon	do

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): 30 साल तक हम जीतते रहे, एक बार जीतने पर इनको इतना घमंड हो गया (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाईयों को बतलाना चाहता हूं कि ये एक 'जीत' को हजम नहीं कर सकते। अब भी लोगों के घरों पर जाकर पत्थर फैकते हैं, नंगा नाच करते हैं (व्यवधान)।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, सी.एम. साहब कौन सा क्वे चन पूछ रहे हैं (व्यवधान)।

Mr. Speaker: Order please. No interruptions. Ch. Mehar Chand may please put his supplementary.

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, मेरे सवाल के पार्ट (सी) के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि डिफिकल्टी गवर्नमैंट के नोटिस में नहीं लाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने अपने लैवल पर कोई सर्वे, कोई इन्क्वायरी करवाई है और यह तसल्ली की है कि जो आर्टिकल्ज देहातों में बनते हैं उनकी सेल होती है या नहीं ? क्या गवर्नमैंट ने अपने लैवल पर कोई सर्वे कंडक्ट करवाया है ?

श्री हरपाल सिंहः हमारे नोटिस में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। वैसे गवर्नमैंट ने डिफ्रेंट एरियाज में या देहात में जहां स्माल स्केल यूनिट्स होंगे उनके लिए परचेज में प्राईसप्रैफरैंस कर रखा है। गवर्नमैंट की तरफ से जो परचेज होगी उसमें यूनिट्स को प्रैफरैंस देंगे अगर कहीं कोई डिफिकल्टी होगी, हमारे नोटिस में लाये, हम हल कर देंगे।

चौधरी मेहर चन्दः मैंने यह पूछा है कि क्या कोई सर्वे कंडक्ट करवाया है, इसका जवाब स्पश्ट आना चाहिए ?

श्री हरपाल सिंहः अगर कोई जरूरत महसूस की गई तो जरूर करवायेंगे।

Construction of Building for Police Station Hassanpur and residential accommodation.

***1738. Sh. Behari Lal Balmiki:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any porposal under consideration of the Government to construct the building for the police station at Hassanpur, District Gurgaon together with the residential accommodation for the Police officials; and

(b) if so, the time by which the buildings as referred to in part(a) above are likely to be constructed?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमति भारदा रानी):

(क) नहीं। इस समय सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव पुलिस स्टे ान हसनपुर जिला गुड़गांव के भवन निर्माण हेतु लम्बित नहीं है। परन्तु सरकार ने एक उप निरीक्षक एक सहायक उप–निरीक्षक, एक मुख्य सिपाही तथा 9 सिपाहियों के लिए रिहाय ी भवन निर्माण की प्र ाासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है जो पुलिस स्टे ान हसनपुर जिला गुड़गांव में निर्मित किये जाने हैं। आ ाा है कि यह निर्माण कार्य मास फरवरी में आरम्भ हो जायेगा।

(ख) रिहाय ी भवनों का निर्माण जिसका उल्लेख उपरलिखित पैरा (क) में किया गया है एक वर्श या उससे कुछ अधिक समय में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, फरीदाबाद टाउन–ि ाप में पुलिस क्वार्टर बनाने के लिए काफी जगह है। क्या मंत्री महोदया वहां पर पुलिस क्वार्टर बनवायेगी ?

श्रीमति भारदा रानीः यह क्वै चन तो हसनपुर के बारे में है। फरीदाबाद के बारे में विचार कर लेंगे। जहां जहां आव यकता होगी विचार कर लिया जाएगा।

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, यहां पर फरीदाबाद–फरीदाबाद की बातें होती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फरीदाबाद में कोई जेलखाना भी खोला जाएगा ? ..... (हंसी)

श्रीमति भारदा रानीः वह किस लिए खुलवाना चाहते हैं ?

श्री के.एन. गुलाटीः जो इस साईड पर हंस रहे है उनके लिए खुलवाना चाहते हैं। ..... (व्यवधान)।

चौधरी राम लाल वधवाः हम तो जेल भुगत आये है अब तुम्हारी बारी हैं ..... (ोर) (व्यवधान)।

Mr. Speaker: Order please. This supplementary does not arise out of this question.

Inaugration of new Block of ESI Hospital at Faridabad

***1742. Sh. K.N. Gulati:** Will the minister for Transport pleased to state-

(a) the date when new Block of ESI Hospital at Faridabad was inaugrated;

(b) the toatl number of beds at present in the new Block as referred to in part (a0 above; and

(c) Whether the staff for the new Block of the Hospitals as reffered to in part (a) above has been provided; if not, the time by which the staff is likely to be provided?

Transport Minister (sh. K.L. Poswal):

(a) 23-3-76.

(b) 90

(c) The Satff is likely to be posted within three months.

Tubewells Connections

***1745. Sh. Amar Singh:** Will the Chief Minister pleased to State-

(a) the total number of Tubewells connections given during the period from 26th June, 1975 to date; and

(b) the district-wise toatal number of applications for Tubewells connections pending at present together with the time by which the tubewells connnections are likely to be given to such applicants?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmonider Singh Chatha):

(a) 16834.

(b) District wise toal number of pending applcations for tubewell connectuions at present are as Under:-

Sr.	District	Number of pending applications for tubewell connections
1	Ambala	905
2	Kurukshetra	2932
3	Karnal	3393
4	Hisar	575
5	Rohtak	500
6	Bhiwani	400
7	Jind	512
8	Sirsa	551
9	Gurgaon	1298
10	Sonepat	615
11	Mohindergarh	2427
Total		14108

The abve pending applications are likely to be cleared during the next financial year i.e. 1977-78.

10.00 बजे

श्री अमर सिंहः अम्बाला जिले में जो 905 एप्लीके ान्ज पैंडिग हैं उनके बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि नैक्सट फाइनाि ायल ईयर में कुनैक ान दिये जायेंगे। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानकारी चाहता हूं कि जिन लोगों की एप्लीके ान्ज पैडिंग हैं और जिन्होंने सरकार से लोन लिया है क्या उनको जल्दी से जल्दी कुनैक ान देने की कृपा करेंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः हमारे पास अम्बाला जिले की 347 टैस्ट रिपोर्ट पैंडिंग हैं। उनको हम बहुत जल्दी से जल्दी कुनैक ान दे रहे हैं। अब हमारे पास केवल 6167 टैस्ट रिपोर्ट पैडिंग हैं ?

चौधरी ि ाव राम वर्माः मंत्री महोदय ने अभी नये कुनैक ान देने की बात कही है, पता नहीं वे नये कुनैक ान कब देंगे या बिल्कुल ही नहीं देंगें। मैं तो मंत्री महोदय से यह जाना चाहता हूं कि जो पहले कुनैक ान दिया हुए हैं क्या उनको पूरी बिजली देने की कृपा करेंगे क्योंकि उनको बहुत थोड़ी देर बिजली दी जाती है ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए बहरहाल इस साल बिजली की इतनी कमी नहीं रही जितनी ये कहते हैं।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः अभी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि 347 टैस्ट रिपोर्ट बकाया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से प्राइवेट टैस्ट रिपोर्टस कितनी है और एम.आई.टी. सी. की कितनी हैं, दूसरे क्या एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज की निि चत तिथि कुनैक ान देने की बता सकते हैं।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज को कुनैक ान देने में हम जरूर प्रेफरैन्स देते हैं।

श्री दलीप सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दो साल पुरानी कितनी ऐप्लीके ान्ज पैंडिंग हैं ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः ये फिगर्ज मेरे पास नहीं है।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक जिले में 5000 पैंडिंग ऐप्लीके ानज में से टैस्ट रिपोर्टस कितनी पैंडिंग हैं ? झज्जर तहसील की ही 500 ऐप्लीके ानज पैंडिंग होंगी और खासकर साहलावास के हल्के में ज्यादा कुनैक ान देने बाकी हैं तो वहीं जल्दी से जल्दी कुनैक ान देने की कृपा करेंगे।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः जिले रोहतक की 149 टैस्ट रिपोर्टस पैंडिंग है इनको हम बहुत ही जल्दी कुनैक ान देंगे।

श्री धज्जा रामः अभी मिनिस्टर महोदय ने डिस्ट्रिक्टवाज कुनैक ान की ऐप्लीके ानज पैंडिंग बताई हैं। मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो किसान लैन्ड मार्गेज से कर्जा लेते हैं और उनको दो महीने या छह महीने तक कनैक ान नहीं मिलता है, किसान को इन्ट्रैस्ट पड़ता रहता है, कया इस इन्ट्रैस्ट को माफ कराने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह बैंक का मामला है। इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

राव बंसी सिंहः जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें 2500 के करीब कनैक ान पैंडिंग हैं, क्या महेन्द्रगढ़ जिले में कनैक ान देने में प्रेफरैन्स दिया जायेगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह बात उनकी ठीक है। पिछली दफा नारनौल, रिवाड़ी, दादरी और झज्जर आदि के एरिया में बहुत ऐप्लीके ानज पैंडिंग थी, हमने दूसरे एरियाज से मैटीरियल डाइवर्ट कर दिया था। अगर फिर भी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम वहां जल्दी से जल्दी कनैक ान देने की कोि ा ा करेंगे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अभी मिनिस्टर साहब ने बताया था कि बिजली की इस साल इतनी कमी नहीं रही। तो मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि करनाल के पास एक झील है जिस पर दिन–रात बिजली जलीती रहती है परन्तु उस झील के साथ ही कई गांव हैं जिनको खेती–बाड़ी के लिए

बिजली की आव यकता हैं वहां बिजली पूरी नहीं दी जाती है। तो क्या पुराने जो पहले के ट्यूबवैल्ज लग हैं उनकी पूरी बिजली दी जायेगी ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: टैस्ट रिपोर्ट पैंड़िंग की बात है, बिजली कितनी मिलती है या नहीं है इस बारे में सवाल नहीं है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय में इन भाइयों से एक ही बात का आ वासन चाहता हूं कि जो रावी–ब्यास के पानी का प्रधान मंत्री जी ने या भारत सरकार ने फैसला किया है उसमें से एक रती भर भी पानी कम नहीं होने देंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: हो सकता है इससे भी ज्यादा पानी ले आयें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: यह बात क्वै चन आवर की नहीं है। सी.एम. साहब को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी वैसे यह फैसला बाबू जगजीवन राम जी ने किया हुआ है, इस फैसले को कौन बदल सकता है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Order please. This is Question Hour. No. arguments please.

श्री ओम प्रका ा गर्ग: अभी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि हम बैकवर्ड एरियाज में कनैक ान जल्दी से जल्दी देंगे और

अगर जरूरत पड़ी तो वहां दूसरी जगहों से सामान डावर्ट करेंगे तो क्या पिछले सालों में जिला कुरूक्षेत्र का सामान दूसरी जगहों पर डायवर्ट तो नहीं कर दिया था जिसके कारण से वहां कनैक ान नहीं दिया जा सके ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः ऐसी बात नहीं है। कुरूक्षेत्र में तो ट्यूबवैल्ज ज्यादा लगते हैं क्योंकि वहां पानी ऊपर है। वहां पर तो हमने सबसे ज्यादा कनैक ान दिये हैं।

चौधरी दल सिंहः क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात है कि कनैक ान देने से पहले जमींदारों से कर्जा मांगते हैं ? क्या सरकार आ वासन देने के लिए तैयार है कि आइन्दा बिजली बोर्ड लोगों से कर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि कई किसान देने में असमर्थ हैं ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि बिजली की तो कमी है लेकिन बिजली की कमी को दूर करने के लिए कई प्रोजैक्ट पर काम चल रहा है इसलिए हरियाणा प्रदे ा को पैसे की आव यकता है। हर प्रकार से पैसा लेने की कोि ा ा की जा रही है। फाइनेन्ाल इन्स्टीच्यू ांज से भी बिजली बोर्ड के लिए पैसा लिया जा रहा है और सरकार को भी बिजली बोर्ड का पैसा देना पड़ता है। यह पैसा बिजली बोर्ड को कर्जे के रूप में देते हैं और बिजली बोर्ड को और भी अधिक धन की आव यकता है इसलिए बिजली बोर्ड की ओर से बांड दिए

जाते हैं। उन बांडो पर बिजली बोर्ड की ओर से बाकायदा इन्ट्रैस्ट दिया जाता है। जो भी किसान भाई या दूसरे बैनिफिसरीज हैं या इंडस्ट्रीयलिल्ट हैं उनको ये बांड दिये जाते हैं ताकि पैसा मिले और उन प्रोजैक्टस को तैयार किया जा सके और बिजलीकी कमी दूर हो। इसलिए यह बांड का पैसा लोगों से लिया जाता है। यह पैसा उनकी मर्जी से लिया जाता है कोई जबरदस्ती नहीं लिया जाता।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः मिनिस्टर साहब ने यहां कहा है कि एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज को जल्दी से जल्दी कनैक्शन देंगे तो मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन ट्यूबवैल्ज की टैस्ट रिपोर्टस आज तक आ चुकी हैं क्या उनको मई से पहले पहले कनैक्शन दे दिये जायेंगे ताकि आने वाली फसल को पानी दिया जा सके ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इस बारे में तो मुझे डेफिनिट पता नहीं कि कितने एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज की टैस्ट रिपोर्ट आ चुकी हैं और कितने की बाकी है।

चौधरी दल सिंहः मुख्य मंत्री साहब से यह बात पूछना चाहता हूं कि जिनके पास पांच एकड़ या दो एकड़ भूमि हैं वे अगर ट्यूबवैल्ज लगाते हैं क्या उनका कर्जा माफ किया जायेगा और जिनके पास ज्यादा जमीन है उन लोगों से ही बिर्जी बोर्ड

कर्जा लेगा दूसरों से नहीं जो दो एकड़ या पांच एकड़ वाले किसान हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ताः इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे।

चौधरी रिजक रामः अभी मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि कर्जा उन लोगों से लेते हैं जिनको कनैक ान देना हो। तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन लोगों ने बिजली बोर्ड के बांडज लिए हुए हैं वे मच्योर भी हो गये है, पीरियड पूरा हो गया है लेकिन वे कै ा नहीं होते हैं। क्योंकि डी.सी. की इजाजत लेनीपड़ती है और वह उसमें रूकावटें डालते हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ताः मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है बांड मच्योर हो गये हैं तो उनकी मर्जी से उनको कन्टीन्यू रखा जायेगा वरना उनकी रकम वापिस कर दी जायेगी।

श्री ओम प्रका ा गर्गः स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन किसानों से सन् 1976 में दो सौ रूपया कर्जे का ले लिया है लेकिन अब 1977 में भी मांग रहे हैं तो क्या इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों से एक बार कर्जा ले लिया है फिर उनसे दुबारा न मांगा जाये।

(कोई उतर नहीं दिया गया)

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जो आ वासन इधर से मांगा गया है, वह तो इन्हें पार्लियामैंट से मांगना चाहिए था। लेकिन मैं तो ....

Mr. Speaker: Order please. Put a supplementary question.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: वही तो मैं कह रहा हूं जी। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो किसानों से जबरदस्ती बांड दिए जाते हैं, बिजली वाले उनसे बिल की पेमेंट नहीं लेते, वह कह देते हैं कि बिल की पेमेंट नहीं लेंगे, पहले बांड लीजिए, क्या यह जबरन बांड लेने बन्द होंगे या नहीं क्योंकि गरीब आदमी बिल देने में भी कठिनाई महसूस करता है और ऊपर से ये 200–300 रूपया बांड का देने को कहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह ज्यादती कब बन्द होगी ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि किसी की अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी तो उससे जबरदस्ती नहीं की जायेगी। जो भी कुछ किया जा रहा है वह किसानों के हित में किया जा रहा है।

Payment made to the Private Printing Pressess

***1747. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Local Government be pleased to state the total amount paid to the Private Printing Presses by State Government for

Government Printing work given to them during the period from 1968-69 to 1976-77 to date separately; together with the names of Presses andthe amount paid in each case, separately?

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी पोखर राम गोदारा):

वर्श 1968–69 से 1976–77 की अवधि के दौरान हरियाणा सराकर द्वारा सरकारी कार्यों की छपाई के लिए गैर–सरकारी प्रैसों को दी गई कुल रा ि ा इस प्रकार है:–

1968–69	34802.98 रूपये
1969–70	701707.24 रूपये
1970–71	903658.28 रूपये
1971–72	1525468.94 रूपये
1972–73	1501369.19 रूपये
1973–74	1305308.24 रूपये
1974–75	1909418.26 रूपये
1975–76	2110300.68 रूपये
1976–77 (31–1–77 तक)	1791012.56 रूपये

संलग्न विवरण पत्र में दिए गए ब्यौरे में प्रैसों के नाम और प्रत्येक प्रैस को दी गई रा ि दिखाई गई हैं।

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1968-69

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Kapur Brothers Delhi	390.00
2	M/s Mehta Dairy Works Delhi	453.07
3	M/s Thomson Press, Delhi	11731.70
4	M/s Markanda Printing Press, Shahbad	1699.29
5	M/s Punjasb Press, Chandigarh	4171.09
6	M/s Ram Lal Kapur & Sons, Delhi	14964.50
7	M/s Ganesh Printing Press, Gurgaon	60.18
8	M/s Haryana Printing Works, Chandigarh	643.25
9	M/s Navjiwan Printing Press, Hissar	689.90
	Amount Paid	34802.98

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1969-70

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Vaishtha Press, Rohtak	106.92
2	M/s Punjab Press, Chandigarh	13794.74
3	M/s Ram lal Brothers & Sons, Delhi	15375.40
4	M/s Haryana Printing Works, Chandigarh	138660.85
5	M/s Agnihotri Printing Works, Chandigarh	286.14
6	M/s Markanda Printing Press, Shahbad	3828.30
7	M/s George Printing Works, Manimajra	563.12
8	M/s Printing Centre, Chandigarh	5911.24
9	M/s Thomson Press, Faridabad	4.901.03
10	M/s Asia Press Chandigarh	13174.25
11	M/s Sh. Shyam Sunder Press, Gurgaon	9061.26
12	M/s Today & Tomarrow Printers,	17262.50

	Faridabad	
13	M/s Mahadevi Onkar Press, Jullundur	53316.34
14	M/s Malhotra Car Manufactured, Delhi	46.35
15	M/s Modern Printers, Karnal	167.23
16	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	1161.80
17	M/s Kapur Brothers Delhi	483.40
18	M/s Bhushan Power Printing Press Jagadhari	12667.30
19	M/s Model Printing Press, Patiala	35520.00
20	M/s Chitwan Printing Press, Jullundur	31990.00
21	M/s Universal Advertiser, Delhi	6000.00
22	M/s Modern Printers, Karnal	460.24
23	M/s Matsya Mundernalaya, Narnaul	355.40
24	M/s Sunrise Printing Press, Jullundur	34923.04
25	M/s Quami Press, Jullundur	19014.70
26	M/s Modert Printers, Jullundur	20013.39

27	M/s Shahadra Printing Press, Shahadra	10805.00
28	M/s New Art Press, ullundur	3745.46
29	M/s Jullundur Co-op. Printing Rubber Society Jullundur	10487.64
30	M/s Jullundur Worksman Ptg. Press Jullundur	6988.00
31	M/s Swan Printing Press, Jullundur	10080.00
32	M/s Arun Press, Muradabad	24362.00
33	M/s Peekay Printers, Jullundur	6469.80
34	M/s Allahabad Law Journal Co. Ltd. Allahabad	163724.20
	Total	701707.24

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1970-71

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Punjab Press, Chandigarh	11899.97
2	M/s Haryana Printing Works, Chandigarh	9331.29

3	M/s The Punjab Mail Press, Chandigarh	275.00
4	M/s Yogesh Printing Press, Jullundur	19093.20
5	M/s Fiends Law Book House, Chandigarh	195.00
6	M/s Thomson Press, Faridabad	41925.81
7	M/s George Printing Press, Faridabad	4008.77
8	M/s Raghbir Printing Works, Chandigarh	880.28
9	M/s Model Printing Press, Patiala	39059.00
10	M/s Swastik Press, Chandigarh	499.00
11	M/s Ram printers and Suppliers Co., Delhi	927.08
12	M/s Mahadevi Onkar Press, Jullundur	2752.10
13	M/s Chitwan Printing Press, Jullundur	140992.35
14	M/s Markanda Printing Press, Shahbad	231.76
15	M/s Asia Press Chandigarh	46240.00

16	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	55935.65
17	M/s Haryana Coop Press, Chandigarh	46098.68
18	M/s Amitabh Printing Press, Chandigarh	437.65
19	M/s Parvesh Printing Press	2609.84
20	M/s Universal Advertiser, Delhi	1877.54
21	M/s Printing Centre, Chnadigarh	403.40
22	M/s Yamuna Press, Chandigarh	204321.57
23	M/s Graphics Centre, Chandigarh	16478.76
24	M/s Bhushan Power Printing Press Jagadhari	152677.54
25	M/s Kapur Brothers, Delhi	1536.12
26	M/s modern Printers, Karnal	22.50
27	M/s Rpshan Lal Block Makers, Chandigarh	805.75
28	M/s Raghu Dayal Pannu Lal, Delhi	880.28
29	M/s Simla Printing Press, Chandigarh	1043.90
30	M/s Universal Art Press, Delhi	14144.45

31	M/s Arun Press, Muradabad	82585.49
32	M/s Bombay Bag Factory, Delhi	3485.55
	Total	9.3658.28

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1970-71

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Punjab Press, Chandigarh	11899.97
2	M/s Haryana Printing Works, Chandigarh	9331.29
3	M/s The Punjab Mail Press, Chandigarh	275.00
4	M/s Yogesh Printing Press, Jullundur	19093.20
5	M/s Fiends Law Book House, Chandigarh	195.00
6	M/s Thomson Press, Faridabad	41925.81
7	M/s George Printing Press, Faridabad	4008.77

8	M/s Raghbir Printing Works, Chandigarh	880.28
9	M/s Model Printing Press, Patiala	39059.00
10	M/s Swastik Press, Chandigarh	499.00
11	M/s Ram printers and Suppliers Co., Delhi	927.08
12	M/s Mahadevi Onkar Press, Jullundur	2752.10
13	M/s Chitwan Printing Press, Jullundur	140992.35
14	M/s Markanda Printing Press, Shahbad	231.76
15	M/s Asia Press Chandigarh	46240.00
16	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	55935.65
17	M/s Haryana Coop Press, Chandigarh	46098.68
18	M/s Amitabh Printing Press, Chandigarh	437.65
19	M/s Parvesh Printing Press	2609.84
20	M/s Universal Advertiser, Delhi	1877.54
21	M/s Printing Centre, Chnadigarh	403.40

22	M/s Yamuna Press, Chandigarh	204321.57
23	M/s Graphics Centre, Chandigarh	16478.76
24	M/s Bhushan Power Printing Press Jagadhari	152677.54
25	M/s Kapur Brothers, Delhi	1536.12
26	M/s modern Printers, Karnal	22.50
27	M/s Roshan Lal Block Makers, Chandigarh	805.75
28	M/s Raghu Dayal Pannu Lal, Delhi	880.28
29	M/s Simla Printing Press, Chandigarh	1043.90
30	M/s Universal Art Press, Delhi	14144.45
31	M/s Arun Press, Muradabad	82585.49
32	M/s Bombay Bag Factory, Delhi	3485.55
	Total	9.3658.28

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1971-72

Sr.	Name of Press	Amount Paid

1	M/s Shahadra Printing Press, Shahadra	87693.46
2	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	60522.36
3	M/s Bhushan Power Printing Press Jagadhari	19125.00
4	M/s Haryana Printing Press, Chandigarh	50.00
5	M/s Simla Printing Press, Chandigarh	576.20
6	M/s Yamuna Press, Chandigarh	93865.96
7	M/s Graphics Centre, Chandigarh	23393.70
8	M/s Kapur Brothers, Delhi	8875.00
9	M/s Krishana Book Binding House, Chandigarh	7844.29
10	M/s Asia Press, Chandigarh	1816.50
11	M/s Mohinder Binding House, Chnadigarh	12.00
12	M/s Thomson Press, Faridabad	50501.10
13	M/s Quami ress, Jullundur	34204.60
14	M/s Amitabh Printing Press, Chandigarh	7059.59

15	M/s Kangra Binding House, Chandigarh	28.00
16	M/s Parveen Binding House, Chandigarh	500.00
17	M/s Arun Press, Muradabad	53719.20
18	M/s Daily Tej Pvt. Ltd., Delhi	89056.80
19	M/s Arvind Printers, Jullundur	4873.50
20	M/s Ashok Press, Moradabad	4139.47
21	M/s Hero Printing Press, Jullundur	4483.00
22	M/s Sunrise Printing Press	177.0
23	M/s National Offset Works, Delhi	109474.90
24	M/s New Sethi Printing Press, Jullundur	39819.00
25	M/s Murari Fine Art works, delhi	74977.23
26	M/s Peekay Printers, Jullundur	557.36
27	M/s Metro Offset printers, Delhi	57650.85
28	M/s Jai Hind Printers, Jullundur	11045.87
29	M/s Modest Printers, Jullundurs	12451.75
30	M/s Chamber Printing Press, Jullundur	10276.10

31	M/s Swan Printing Press, Jullundur	2097.02
32	M/s Bajaj Binding House, Karnal	1607.76
33	M/s Kishan Book Binding House, Gurgaon	1434.40
34	Printing India, Chandigarh	1222.10
35	Controller, ptg. & Sty. U.T., Chandigarh	64238.24
36	M/s Gem Printers, Jullundur	12567.81
37	M/s Eagle Offset Printers, Delhi	16664.54
38	M/s Hindustan Offset Press, Delhi	5227.74
39	M/s Allahabad law Journal Co., Allahabad	34043.50
40	M/s Bhargava Press, Allahabad	55455.00
41	M/s Bhrigu Press, Allahabad	40033.00
42	M/s Sumar Printing Press, Delhi	30763.50
43	M/s Ganesh Printing Press, Gurgaon	18813.50
44	M/s Santosh Art Press, Gurgaon	12113.80
45	M/s Rohtak Printing Press, Gurgaon	17944.60
46	M/s Gerorge Printing Works, Manimajra	35145.50

47	M/s Chandigarh Times Press, Chandigarh	15738.00
48	M/s Sanatan Dharam Press, Manimajra	14184.00
49	M/s Paradise Printers, Chandigarh	20465.00
50	M/s Dominion Press, Chandigarh	13058.00
51	M/s Lily Art Press, Chandigarh	6940.00
52	M/s Navjiveewabn Press, Hissar	25696.00
53	M/s United Printing Press, Gurgaon	32669.20
54	M/s Vikas Printing Press, Rohtak	23964.50
55	M/s Paradise Printers, Delhi	31800.50
56	M/s Shashi Printing Press, Delhi	24652.70
57	M/s Billu Printers, Manimajra	6890.60
58	M/s lalit Press, Chnadigarh	4298.00
59	M/s Lucky Printers, Chandigarh	16924.00
60	M/s Great India Press, Chnadigarh	14718.00
61	M/s O.K. Printing Press, Chnadigarh	6127.60
62	M/s Gogi Printers, Chandigarh	7129.00
63	M/s Sh. Shyam Sunder Pres,	10228.04

	Gurgaon	
64	M/s New Stylish Printers, Gurgaon	14959.50
65	M/s Sushma Art Printers, Gurgaon	16959.50
	Total	1525468.94

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1972-73

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Kapur Brothers, Delhi	538.00
2	M/s George Printing Works, Manimajra	1019.34
3	M/s K.Kumar and Co., Delhi	54013.65
4	M/ss Yamuna Press, Chandigarh	15053.79
5	M/s Paradise Printers, Chandigarh	4704.20
6	M/s Mahadevi Onkar Press, Jullundur City	880.30
7	M/s Bhushan Power Printing Press, Jagadhari	102992.75
8	M/s Thomson Press, Delhi	122394.20

9	M/s Ess Tee Printers, Juulundur City	4011.40
10	M/s Quami Pres, jullundur city	170245.10
11	M/s Sterling Printers, Chnadigarh	336.88
12	M/s S.D. Press, Msanimajra	4212.05
13	M/s National Offset Works, New Delhi	51540.65
14	M/s Arun Press, Moradabad	26919.80
15	M/s Daily Tej Pvt. Ltd., Delhi	35976.34
16	M/s Sarswati Offset Printers, Delhi	97247.10
17	M/s Swan Printing Press, Jullundurs	38521.03
18	M/s Chamber Printing Press, Jullundur	24575.41
19	M/s Shashi Printing Press, Jullundur	16877.63
20	M/s Eagle Offset Printers, Delhi	60522.59
21	M/s New Sethi Printing Press, Julundur	33131.81
22	M/s Kesar kairi Electric Press, Delhi	20816.30
23	M/s Jullundur Coops. Ptg. Press,	32481.90

	Jullundur	
24	M/s Peelay Printers, Jullundur	27062.50
25	M/s Metro Offset Printers, New Delhi	80655.39
26	M/s Shahadra Printing Press, New Delhi	53876.34
27	M/s Rastriya Electric ress, Jullundur	11950.40
28	M/s Gem Printers, Jullundur	10762.08
29	M/s Sharda Printers, Hissar	1785.54
30	M/s Hindustan Offset Works, Delhi	30640.05
31	M/s A.J. Printers, Delhi	4678.10
32	M/s Murari Fine Arts Press, Delhi	40613.11
33	M/s Calenders Maker, Delhi	17503.48
34	M/s Ashoka Printing press, Modinagar	11552.95
35	M/s Arvind Press, Jullundur	771.20
36	M/s Modest Printers, Jullundur	11270.70
37	M/s Delhi Press, New Delhi	7376.67
38	M/s Mehta Art Press, Delhi	11664.67

39	M/s Ajanta Offset Works, New Delhi	59569.85
40	M/s National Coops. Ptg. Press, Chandigarh	394.15
41	M/s Parvesh Printing Press, Chandigarhs	5505.25
42	M/s New Art Press, Jullundur	7443.55
43	M/s Delhi Book Binding House	3350.00
44	M/s Quality Law Binding House	32.00
45	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	50.839.40
46	M/s Universal Advertiser, New Delhi	12016.24
47	M/s Allahabad law Journal, Allahabad	69160.00
48	M/s Bhirgu Press, Allahabad	68628.00
49	M/s Bhargav Press, Allahabad	38229.00
50	M/s Krishna Book Binding House, Chnadigarh	15885.00
51	M/s graphic Centre, Chnadigarh	46589.43
52	Controller, Ptg. & Sty. U.T., Chandigarh	5782.04
	Total	1501369.19

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1973-74

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Printing Press, Chandigarh	376.90
2	M/s S.D. Press, Manimajra	11536.23
3	M/s Graphic Centre, Chandigarh	56825.83
4	M/s Paradise Printers, Chandigarh	10653.75
5	M/s Associated Printers, Chandigarh	25813.08
6	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	43305.20
7	M/s lalit Press, Chandigarh	3032.49
8	M/s Lucky Press, Chandigarh	792.30
9	M/s Simla Printing Press, Chnadigarh	1407.00
10	M/s Goel Press, Chandigarh	1614.40
11	M/s George Printing Press, Manimajra	4643.10
12	M/s Jawahar Printing Press, Chandigarh	5295.80

13	M/s Arun Book Binding House, Candigarh	4817.00
14	M/s Atma Book Binding House, Chandigarh	1405.00
15	M/s general Traders & Suppliers, Chandigarh	10350.00
16	M/s Vijay Binding House, Chandigarh	4205.73
17	M/s National Binding House, Chandigarh	7589.55
18	M/s Allied Drawing Store, Bombay	28394.63
19	M/s New Sethi Printing Press, Jullundur	20749.10
20	M/s K. Kumar and Co., Delhi	20812.75
21	M/s Shahdras Printing Press, Delhi	4633.00
22	M/s Sunrise Printing Press, Jullundur	3300.00
23	M/s New Art Press, Jullundur	21555.70
24	M/s Allahabad Law Journal Co., Allahabad	19298.55
25	M/s Bhargava Press, Allahabad	71213.90
26	M/s Swastik Mudernalya, Allahabad	105953.00

27	M/s Bhirgu Press, Allahabad	13459.00
28	M/s Bhushan Power Printing Press, Jagadhari	25573.90
29	M/s Quami Press, Jullundur	10899.00
30	M/s Kapur Brothers & Sons, Delhi	3118.00
31	M/s Universal Advertiser, Delhi	541.87
32	M/s Sarswati Offset Printer, Delhi	117099.90
33	M/s Thomson Press, Faridabad	68379.20
34	M/s Book Craft, Delhi	1250.00
35	M/s Delhi Book Binding House, Delhi	1644.50
36	M/s Agnihotri Works, Ambala	72.10
37	M/s Statesman, Delhi	1045.18
38	M/s shuchi Press, Delhi	7939.50
39	Shri Shyam Sunder Press, Gurgaon	4736.55
40	M/s Jullundur Coops, Jullundur	16600.00
41	M/s Metro Offset Printers, Delhis	85290.70
42	M/s Arun Press, Muradabad	33833.10
43	M/s Punjab National pres, Delhi	15410.20

44	M/s Eagle Offset Printing, Delhi	107453.19
45	M/s Ajanata Offset, Delhi	15901.41
46	M/s Hindustan Offset Press, Delhi	28242.75
47	M/s New Art Press, Jullundur	5254.00
48	M/s S. Naraian & sons, Delhis	4159.00
49	M/s Delhi Tej Pvt. Ltd.s, Delhi	12653.00
50	M/s Murari Fine Arts Works, Delhi	2668.00
51	M/s Shahdra Press, Delhi	14599.00
52	M/s National Offset Works, Delhi	45088.50
53	M/s Universal Art Press, Agra	1234.00
54	M/s Bharat Prakashan Udiyog, Delhi	94693.70
55	M/s Jayyad Press, Delhi	78055.00
	Total	1305308.24

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1974-75

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Bharat Prakashan Udiyog,	385774.10

	Delhi	
2	M/s Sarswati Offset Printer, Delhi	21032.35
3	M/s Associated Printers, Chandigarh	86938.93
4	M/s Metro Offset Printers, Delhi	161279.00
5	M/s Eagle Offset Printing, Delhi	165606.20
6	M/s New Sethi Printing Press, Julundur	10044.23
7	M/s Delhi Tej Pvt. Ltd., Delhi	79524.75
8	M/s Radha Press, Delhi	78404.20
9	M/s Ajanata Offset, Delhi	72863.35
10	M/s Paradise Printers, Chandigarh	5652.32
11	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	77061.59
12	M/s Lucky Press, Chandigarh	20320.20
13	M/s Graphic Centre, Chandigarh	50058.94
14	M/s lalit Press, Chandigarh	18104.27
15	M/s Sunil Book Binding House, Chandigarh	21369.00
16	M/s S.D. Press, Chandigarh	15283.50

17	M/s O.K. Printing Press, Chandigarh	3735.50
18	M/s Jawahar Printing Press, Chnadigarh	52100.20
19	M/s General Traders & Suppliers, Chandigarh	8100.00
20	M/s Printing entre, Chandigarh	1802.37
21	M/s Akhand Bharat Printers, Chandigarh	5660.15
22	M/s george Ptg. works, Chandigarh	6303.25
23	M/s s Allahabad Law Journal Co., Allahabad	49351.60
24	M/s Bhirgu Press, Allahabad	131078.50
25	M/s Bhargava Press, Allahabad	164172.00
26	M/s Yamuna Press, Chandigarh	6900.30
27	M/s Bali Art Press, Faridabad	145959.85
28	M/s Bhushan Power Printing Press, Jagadhari	4359.80
29	M/s Yogendra Press, Chandigarh	7043.10
30	M/s S. Naraian & sons, Delhi	89.03.25
31	M/s Swastik Mudernalya, Allahabad	23585.00

32	M/s Paradise Printers, Delhi	13306.85
33	M/s Navjiean Printing Press, Hissar	477.50
34	M/s Quami Press, Jullundur	8263.80
35	M/s Shahadra Printing Press, Delhi	16489.10
36	M/s Vikas Printing Press, Rohtak	9314.25
37	M/s Ganesh Printing Press, Gurgaon	11709.00
38	M/s Kuldeep Press, Ambala Cantt.	1105.50
39	M/s Shyam Sunder Press, Gurgaon	8693.30
40	M/s Bhushan Power Printing Press, Jagadhari	3381.50
41	M/s Calender Maker Corp., Delhi	13129.37
42	M/s sunrise Printing Press, Jullundur	5084.50
43	M/s K. Kumar & Co. Delhi	30094.35
44	M/s New Art Press, Jullundur	7761.00
45	M/s Paradise Printers, Chnadigarh	11085.20
46	M/s Haryana saket Council Press, Chnadigarh	681.05
47	M/s Billu Printers, chandigarh	5101.35
48	M/s Goel Press, Chandigarh	1055.30

49	M/s Peco Printing Press, Chandigarh	487.90
50	M/s Arun Book Binding House, Chandigarh	3935.60
51	M/s Greater Punjab Press, Chandigarh	890.00
	Total	1909418.26

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1975-76

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Akhand Barat Printers, Chandigarh	5792.60
2	M/s sanatan Dharam Press, Manimajra	10937.41
3	M/s M.R. Printing Press, (Bhadurgarh) Rohtak	11239.55
4	M/s Bali Art Press Faridabad	13718.65
5	M/s Associated Printers, Chandigarh	26674.00
6	M/s Peoples quality Printers, Hissar	35872.85

7	M/s Lucky Printers, Chandigarh	11573.12
8	M/s Paradise Printers, Delhi	28562.50
9	M/s vikas Printing Press, rohtak	14266.32
10	M/s Paradise Printers, Chandigarh	13645.12
11	M/s S. Narian & sons, Delhi	10731.37
12	M/s Dominion rinting press, Chandigarh	1100.87
13	M/s Navjiwan Printing Press, Hisar	7242.37
14	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	58219.05
15	M/s Printing Centre, Chandigarh	1938.75
16	M/s Chandigarh Times, Manimajra	3142.60
17	M/s George Printing Press, Manimajra	13696.00
18	M/s Santosh Art Press, Gurgaon	7925.87
19	M/s Ganesh Printing Press, Gurgaon	14878.50
20	M/s Jawahar Printing Press, Chandigarh	50286.50
21	M/s paul Printing Press, Ambala Cantt.	1867.25
22	M/s O.K. Printinmg Pres,	105.50

	Chnadigarh	
23	M/s Shri Shyam Sunder Press, Gurgaon	11868.75
24	M/s New stylish Printer, Gurgaon	2638.47
25	M/s Yours Qualitry Printer, Hissar	3412.24
26	M/s Sushma Atrt Press, Gurgaon	4616.55
27	M/s United Printing Press, Gurgaon	9114.75
28	M/s Sunrise Printing Press, Jullundur	1750.00
29	M/s Quami Press, Jullundur	22850.35
30	M/s J.V. Navlakhi & Co., Bombay	22907.20
31	M/s New Art Press, Jullundur City	13481.15
32	M/s Greater Punjab Press, Chnadigarh	3660.50
33	M/s Vijay Printing Press, Mathura	16915.52
34	M/s General Traders & Suppliers, Chnadigarh	8568.24
35	M/s Swan Printing Press, Jullundur	265.70
36	M/s Haryana Coops. Union Press, Chandigarh	15625.98
37	M/s Caxton Press, Allahabad	175350.63

38	M/s Bhargava Pres, Allahabad	160475.65
39	M/s Allahabad Law Journal, Alllahabad	162206.42
40	M/s anoop Printing Press, Allahabad	19823.00
41	M/s Law Printing Press, Allahabad	188526.50
42	M/s Swastik Mudernalya, Allahabad	42400.00
43	M/s Bhrigu Press, Allahabad	100767.00
44	M/s Bilu Printers, Manimajra	4369.50
45	M/s Bhushan Power Printing Press, Jagadhari	62670.50
46	M/s Saraswati Offset Printers, New Delhi	10024.20
47	M/s Book Binding Works, Manimajra	5888.80
48	M/s Kuldip Press, Ambala	3950.00
49	M/s M/s evergreen Enterprise, New Delhi	540.04
50	M/s Asia Pres, Chandigarh	522.00
51	M/s Jai Hind Printing Press, Jullundur	25700.93
52	M/s Indian Printing Works, Delhi	13704.40

53	M/s National Offset Works, New Delhi	61394.75
54	M/s Murari Fine Arts Works, Delhi	42799.02
55	M/s Indian law Book Binding Works, Chnadigarh	17571.80
56	M/s Punjab National Works, Delhi	137106.40
57	M/s Arsons Photo Ofset Printers, new Delhi	3480.45
58	M/s Bharat Parkashan Udiyog, Delhi	54551.75
59	M/s Tayal Enterprise, Delhi	105798.15
60	M/s Thomsons Press, Delhi	2573.05
61	M/s Aaed Book Binding House, Chnadigarh	3561.00
62	M/s Sunil Book Binding House, Chnadigarh	2421.25
63	M/s Nischal Printing Press, Yamunanagar	4234.05
64	M/s Panchkula Press, Panchkula	2361.00
65	M/s Govt. of India Press, Chnadigarh	93179.00
66	M/s K. Kumar & company, Delhi	10578.65

67	M/s national Binding House, Chandigarh	29008.50
68	M/s Graphic Centre, Chnadigarh	65055.82
69	M/s New Sethi Printing Press, Jullundur	7362.20
70	M/s The Lalit Press. Chandigarh	6017.10
	Total	2110300.68

Statement showing amount paid to private presses for printing work during the year 1976-77 up to 31-1-77

Sr.	Name of Press	Amount Paid
1	M/s Allahabad Law Journal Co. Ltd. Allahabad	30000.00
2	M/s indian Law Book Binding Works, Chnadigarh	13665.70
3	M/s Annop Printing Press, allahabad	71075.00
4	M/s Eagle Offset Printers, Delhi	38046.00
5	M/s peekay Printers, ullundur	384.55
6	M/s Bhushans Power Printing Press,	259443.10

	Jagadhari	
7	M/s Azad Book Binding House, Chandigarh	2599.30
8	M/s Akhand Bharat Printers, Chandigarh	12942.15
9	M/s Bhrigu Press, Allahabad	43270.74
10	M/s Dominimon Press, Chandigarh	9034.77
11	M/s Bhargava Pres, Allahabad	197526.30
12	M/s Girdhar Printing Press, Chandigarh	22127.30
13	M/s Himachal power Printig Press, Solan	72464.00
14	M/s Swastik Mudernalya, Allahabad	87449.30
15	M/s GeorgePrinting press Works, Manimajra	986.14
16	M/s Nischal Printing Press, Yamunanagar	2517.90
17	M/s Vijay Binding House, Chandigarh	1600.00
18	M/s The Jullundur Co-operating Printing and Publishing Society Ltd., Jullundur	753.55

19	M/s Sanatam Dharam Press, Manimajra	21106.35
20	M/s Caxton Press, Allahabad	116763.00
21	M/s Associated Printers, Chnadigarh	37443.30
22	M/s Jawahar Printing Press, Chandigarh	38219.20
23	M/s Lalit Press, Chandigarh	9592.41
24	M/s Sharma machine Printing press, Moradabad	4155.25
25	M/s Vikas Printing Press, Rohtak	21159.92
26	M/s Law Printing Press, Allahabad	43149.65
27	M/s Ganesh Printing press, Gurgaon	12074.00
28	M/s Jai Hind Printing Press, Jullundur	19607.00
29	M/s Paradise Printers, Chnadigarh	20881.00
30	M/s Sunrise Printing Press, Jullundur	11461.80
31	M/s R.K. Printers, Jaipur	13779.80
32	M/s New Sethi Printing Press, Jullundur	108452.10
33	M/s sunil Book Biondig Works,	4800.00

	Chandigarh	
34	M/s Pawan law Book Binding Works, Chnadigarh	1600.00
35	M/s Kewals Printing Press, Amritsar	91291055
36	M/s Kewal Printing Press, Amritsar	3420.20
37	M/s Book Binding Centre, Chandigarh	1225.00
38	M/s Lucky Printers, Chandigarh	21848.12
39	M/s shri Shyam Sunder Press, Gurgaon	5631.95
40	M/s Panchkula Printers, Panchkula	13805.85
41	M/s Goel Press, Manimajra	1171.00
42	Controller, Ptg. & Sty. U.T., Chandigarh	364.48
43	M/s sarswati Offset Printers, New Delhis	250.00
44	M/s M.R. Printing Press, Bhadurgarh	25228.08
45	M/s Billu Printers, Manimajra	10939.80
46	M/s New Stylish Printers, Gurgaon	7755.00
47	M/s Shushma Art Press, Gurgaon	8915.37

48	M/s People Quality Printers, Hissar	21913.47
49	M/s Navjiwan Printing Press, Hissar	22941.00
50	M/s Great India Press, Chandigarh	6324.15
51	M/s Chandan Electric press, Kalka	8656.50
52	M/s Gogio Press, Chandigarh	5486.22
53	M/s O.K. Printing Press, Chandigarh	8370.20
54	M/s Lake art Press, Chandigarh	9182.75
55	M/s santosh Art Press, Gurgaon	8972.45
56	M/s N.V. Printers, Rewari	8140.30
57	M/s Agnihotri Works, ambala Cantt.	83.20
58	M/s ashok Mudaran Girh, Allahabad	26770.60
59	M/s Aggarwal Paper Convertors, Ghaziabad	23283.90
60	M/s Printing Service Company, Manimajra	343.00
61	M/s Kuldip Press, ambala Cantt.	300.00
62	M/s Rama Plastic Industries, Delhi	503.39
63	M/s Murari fine Art works, Delhi	4834.35
64	M/s Pitamber Book Depot, Delhi	3200.00

65	M/s Graphic Centre, Chandigarh	52093.15
66	M/s Suraj Art Press, Allahabad	28881.45
67	M/s Printing Centre, Chandigarh	8755.50
	Total	1791012.56

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो काम प्राइवेट प्रैसों को दिया जाता है, उसको देने का प्रोसीजर क्या है ? यानी उनको काम अलाट करने का क्राइटेरिया क्या है ?

चौधरी पोखर राम गोदाराः जो सरकार का ज्यादा काम होता ह, वह प्राइवेट प्रैसों को दिया जाता है।

चौधरी राम लाल वधवाः मैंने यह पूछा है कि प्राइवेट प्रैसों को काम देने का प्रोसीजर क्या है ?

चौधरी पोखर राम गोदाराः हम टैन्डर मांगते हैं, जिसका लोएस्ट टैन्डर होता है, उसको हम काम दे देते हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टैंडर किसी अखबार में निकाले जाते हैं या किन्ही चन्द प्रैसों को लिखकर ही बता दिया जाता है कि आप हमें अपने टैन्डर भेज दो ?

चौधरी पोखर राम गोदाराः बाकायदा अखबारों में छपवाये जाते हैं।

Mr. Speaker: The Question Hour is over.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, हमें उन अन–स्टार्ड क्वै चन्ज का भी अभी तक जवाब नहीं मिला जो आज की लिस्ट पर थे।

Mr. Speaker: I will look into it.

अतारांकित प्र न एवं उतर

Land lying unutilised beyond tail No. 24 of Kheri Sadh distributary.

567. Mahant Shreyo Nath Yogi: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether any unutilised land is lying beyond tail No. 24 of Kheri Sadh Distributary which was previsouly called as Ismaila Branch;

(b) if so, whether the land as referred to in part(a) above is likely to be restored to those persons from whom the same was acquired at the time of constructing the canal; and

(c) if reply to part (b) above be in the negative, the purpose for which the land as referred to in part(a) above is to be utilised?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) हां

(ख) तथा (ग) इस भूमि के निपटान के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

Extending of Local Bus Service from Medical College, Rohtak to Tourist Complex

***568. Mahant Sheryo Nath Yogi:** Wil be Minister for Transport be pleased to state whether the local bus service plying up to Medical College, Rohtak is likely to be extended upto tourist complex?

परिवहन मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): टूरिस्ट कम्पलैक्स रोहतक में निर्माणधीन हैं। ज्योंहि यह पूर्ण होगा आव यकतानुसार अलग स्थानीय बस सेवा चलाई जाएगी।

Ayurvedic Degree Colleges

569. Mahant Shreyo Nath Yogi: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the number of Ayurvedic Degree College in Haryana as at present;

(b) the number of beds provided in each of the Hospitals attached to the Ayurvedic Degree Colleges mentioned in part (a) above; and

(c) the number of beds required to be provided to a student under rules in such colleges?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह):

(ए) पांच

(बी) (क) श्री मस्तनाथ आर्युवैदिक कालिज अस्थल बोहर, रोहतक। 120 (40 बिस्तरें आर्युवैदिक इलाज के लिए 80 बिस्तरे मिश्रित इलाज के लिए)

(ख) श्री कृश्णा आर्युवैदिक कालिज करूक्षेत्र 20

(ग) महिला आर्युवैदकि कालिज खानपुर कलां सोनीपत 20

(घ) जनता आर्युवैदकि कालिज, भुटाना सोनीपत 8

(ड़) गौड़ ब्राहाण आर्युवैदकि कालिज, रोहतक

(सी) प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक बिस्तर।

Construction of Memorials of Martyrss.

570. Mahant Shreyo Nath Yogi: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether any land of Asthal Bohar Math was acquired for construction a memorial for Martyrs; and

(b) if so, whether the construction work has been started; if not, the reasons therefor, together with the totla expenditure which is likely to be incurred on the memorial as referred to in part (a) above?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) हां

(ख) नहीं। कच्चा अनुमान बनाया जा रहा है।

Improvement in quality and supply of people's cloth

571. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state:-

(a) the steps, if any, taken for the improvement in quality of people's cloth and supply there of in the State under the 20 Point Programmed of the Prime Minister; and

(b) the quantity of cloth distributed to the people through Ration Depots in each district of the State during the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 todate, separately?

कराधान तथा आबकारी मंत्री (श्री भयाम चन्द):

(क) सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे तथा

(ख) वि ेश लाभ न होगा।

Misuse of Import Licences

577. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will te Minister for Industries be pleased to state the district wise number of cases of misuse of Import Licences detected in the State during the period from 1st June, 1975, todate, together wiht the action taken and results thereof?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह): एक विवरणी संलग्न है।

विवरणी

1–6–1975 और 28–2–1977 के बीच के समय में आयात लाईसैंस के दुरूपोग, सन्देहपूर्ण दुरूपोग के 57 केसिज उद्योग विभाग के नोटिस में आए। ये निम्नलिखित जिलौं से सम्बन्धित हैं:–

1	गुड़गावां	36
2	सोनीपत	6
3	महेन्द्रगढ़	4

4	भिवानी	4
5	करनाल	3
6	रोहतक	3
7	अम्बाला	1

इन सभी 57 केसिज के विशय में भारत सरकार, जो कि ऐसे केसजि में उचित कार्यवाही करने के लिए सक्ष्म प्राधिकारी हैं, को रिपोर्ट कर दी गई है। 42 केसिज में पार्टीज को या तो आगे आयात सुविधायें प्राप्त करने से Debar कर दिया गया है या उनको लाईसेंसिग प्राधिकारी ने Alert List में डाल दियसा है। भोश 15 केसिज लाईसेंसिंग प्राधिकारी के पास उचित कार्यवाही हेतू लम्बित पड़ें हैं।

House sites for Landless and weakker section

578. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) the steps, if any, taken by the State Government to provide house sites to landless and weaker sections in the rural areas of the State under the 20-Point Programme of the Prime Minister; and

(b) the districtwise total number of house-sites allotted/distributed to the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other landless persons of the State from the announcement of the above mentioned 20-Point Programme to date, separtely?

राजस्व मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक):

(क) अनुलग्नक क – सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(ख) अनुलग्नक ख – सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

अनुलग्नक – क

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के निकट या उसके अन्दर स्थित भाामलात भूमि में से प्रत्येंक भूमिहीन अनुसूचित जाति तथा अधिसूचित पिछड़ें वर्ग के सदस्यों को 100 वर्ग गज आवास स्थल मुफ्त दिए गए हैं। उन ग्रामों में जहां भाामलात भूमि उपलब्ध नहीं थी, पात्र व्यक्तियों को प्लाट अलाट करने हेतू अभिग्रहण की गई है। सरकार ने इन रिहाय ाी प्लाटों के हस्तान्तरण पर रजिस्ट्रे ान फीस तथा स्टैम्प ड्यूटी से छूट दे दी है।

अनुलग्नक – ख

क्र.	जिला का	व्यक्तियों को 31–1–1977 तक अलाट

सं.	नाम	किए गए/ बांटे गये आवास स्थल की संख्या		
		अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग	जोड़
1	2	3	4	5
1	अम्बाला	5300	3388	8688
2	कुरूक्षेत्र	6860	3058	9918
3	करनाल	22138	17650	39788
4	सोनीपत	11190	8684	19874
5	रोहतक	16450	7223	23673
6	हिसार	18008	6704	24712
7	सिरसा	9637	3187	12824
8	भिवानी	8204	3666	11870
9	गुड़गांव	18883	14008	32891
10	महेन्द्रगढ़	7991	4638	12629
11	जीन्द	11469	5305	16774

	जोड़	136130	77511	213641

Loans granted by the Haryana Financial Corporation

579. Ch. ram Lal Wadhwa: will the Minister for industriess be pleased to state-

(a) the district-wise total number of applications for the grant of loans recieved and disposed of by the Haryana Financial Corporations during the period from 1st October, 1975 to 31st December, 1976, seperately, together with the number of such applications still pending for disposal; and

(b) the district-wise names and addresses of the persons who appied for the loan as referred to in part (a) above together with the amount of loan granted in each case?

Industries Minister (Sh. harpal Singh):

(a) A statement (Annexure I) is laid on the Table of the House.

(b) A statement (Annexure I) is laid on the Table of the House.

ANNEXURE-I

Sr.	Name of Distt.	No. of applications

		Recieved during 1-10-75 to 31-12-76	Disposed of during 1-10-75 to 31-12-76	still pending for disposal as on 31-12-76
1	2	3	4	5
1	Ambala	24	20	4
2	Bhiwani	17	13	4
3	Gurgaon	50	40	10
4	Hissar	19	13	6
5	Jind	8	5	3
6	Karnal	26	21	5
7	Kurukshetra	6	5	1
8	Mohindergarh	10	8	2
9	Rohtak	9	6	3
10	Sirsa	12	9	3
11	Sonepat	15	14	1
Total		196	154	42

ANNEXURE- II

Sr.	Distt.Name & Address of the peron who applied for loan	Amount of Loan granted
1	2	3
	AMBALA	
1	M/s Gurunanak Cold Storage, Jurian, Teh, Jagadhri	70000
2	M/s Modern Ex-Servicemen Engg. Co., Industrial Estate, Panchkula	182000
3	M/s Inder Cold Storage, Near Rly. Station, Mustafabad	300000
4	M/s Lapfast Abrasive Productss, 278, Indl. Estate, Panchkula	200000
5	M/s Globe Engg. Works, 17, Indl. Estate, Ambala City	182000
6	M/s atker Industries, B-52, HMT Colony, Pinjore	162000
7	M/s Pashupati Industries Ancillary Indl. Estate, Panchkula	265000
8	M/s Dass Ebnterprise, Ancillary Indl. Estate, Panchkula	287000
9	M/s ajay Industrial Corpn. Ancillary Indl. Estate, Panchkula	421000

10	M/s Bharat Oil & General Mills, E-26, Ids. area, Yamunagar	155000
11	M/s Hindustan Thermoplastics, 5, Indl. Estate, Jagadhari Road, ambala cantt.	580000
12	M/s Sukata Industrial Corporantion, 1, Indl. Estate, Pinjore.s	280000
13	M/s Narian Rice & General Mills, P.O. Khizrabad East, Teh. Jagadhri	250000
14	M/s C. Lal Electrical & Mechanical, 1-2, Indl. Estate, ambala City	482000
15	M/s Chopra steel Industries, Nahan Road, Nariangarh	40000
16	M/s Dashmesh SawMills, 59, Indls. Estate, Y. Nagar	107000
17	M/s Yamuna Gases Pvt. Ltd., Jagadhri	236000
18	M/s switch Gear Inds. 747, Mahabir Colony, Y. Nagar	Withdrawn
19	M/s Himalaya Straw Board Mills, Nahan road, Nariangarh	Do
20	M/s Goel Khandsari Udyog,	Do

	Barara.	
21	M/s Munshi ram & Sons, Lakhaura, Teh, Nariangarh	Pending
22	M/s Harve Metals (India) Pvt. Ltd., C-319, Defence Colony, New Delhi (Factory at Panchkula)	Do
23	M/s K.K. & Co. engineers & Fabricators, 221, Sector-9C Chandigarh (Factory at Panchkula)	Do
24	M/s Jamna Auto Inds. Jai Road, Indl. Area Y. Nagar	Do
BHIWANI		
1	M/s Haryana Agr. Impl. Industries, Siwni Mandi	150000
2	M/s United iron & Re-Rolling Inds, Chiripal Strret, Bhiwani	121000
3	M/s Krishana Paints& Chemicals Plot No.1, Indl. Areas, Rohtak Road, Bhiwani	262000
4	M/s Lalwaney Steel Fabricators, Plot No. 6, Indl. Area, Bhiwani	125000
5	M/s Jain Spun Pipe Company, Malluwasa.	250000

6	M/s Shree Sarswati Spinning Mills, P.O. Birla Colony, Bhiwani	700000
7	M/s Shree Krishana Textile & General Industries, Plot No. 1 Indl. Development Colony, Bhiwani	288000
8	M/s Modern Inds., I.A., Bhiwani	124000
9	M/s Dilip Oil Mills, V. Dhanana (Distt. Bhiwani)	148000
10	M/s Anupama Chemicals, Naya Bazar, Bhiwani	27000
11	M/s Vikas Gram dal & ginning Factory, Siwani mandi	120000
12	M/s Sharma Woollen Inds. Toshama	Withdrawn
13	M/s United Mineral Inds. Shanker market, Ch. Dadri	Do
14	M/s Woony Udyog Limited Inds. Sector-21, Bhiwanis	Pending
15	M/s Wooltex India, 510, Ansal Bhwan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi (Factory at Bhiwani)	Do
16	M/s Haryana Rubber & Tyres Inds. 26/87, Didwana Temple Baroi Gate, Bhiwani	Do

17	M/s Hari Engg. Works, Siwani Road, Tosham	Do
	GURGAON	
1	M/s Electrokem Enterprises, 55, I.E., Gurgaon	324000
2	M/s Intra Chemicals & drugs Pvt. Ltd., I.D.C., Mehraulli Road, Gurgaon	735000
3	M/s Spring & Stamping Incorporated 22-B, I.A., Faridabad	195000
4	M/s Mona agro Chemical (P) Ltd., Ballabgarh	1170000
5	M/s Paji Machine Tools, Plot No. 7, BH-5, Faridabad	160000
6	M/s Adheses & Allied Inds., 124-A	215000
7	M/s S.K. Surgical (p) Ltd., 81, H.S.I.D.C., Indl. Complex Gurgaon Palam Road, Gurgaon	830000
8	M/s Super Alloys Cast, Plot no. 62, sector 6, Fardidabad	846000
9	M/s Microbe Laboratories, 13, Indl. Area, N.I.T., Faridabad	295000
10	M/s Haryana Potteries, G.T. Road,	130000

	Aurangabad, Teh. Palwal	
11	M/s East India Commercial Co. Pvt. Ltd, New Delhi, House 27, Bharhakambha Road, New Delhi-1 (Factory Faridabad)	207000
12	M/s ramanand Parmanand Hissaria Bazar, sirsa (Factory at Faridabad)	780000
13	M/s Thermadyne Pvt. Ltd., 18, Boulvard Road, Delhi, (Factory at Faridabad)	145600
14	M/s Jullundur Auto Mfg. Co.4, I.E., Delhi road, Gurgaon	1600000
15	M/s electro Matter Inds. plot No. 384, sector-24, Faridabad	140000
16	M/s Faridabad Auto Inds. Pvt. Ltd., 63, Sector-6, Faridabad	500000
17	M/s Super Steel Forgings Plot No. 34, sector-6, Faridabad.	610000
18	M/s Haryana Chemical Inds. P.Ltd., 12th Mile Stone, Mathura Road, Faridabad	230000
19	M/s Clutch Auto P. Ltd., 304, Rohit House Tolstoy Marg, New	975000

	Delhi (Factory at Faridabad)	
20	M/s Rattan Chand Harijas rai P. Ltd.,64 Indl. Estate, Faridabad	555000
21	M/s Hindustan Kokoku Wire Ltd., 64, Indl. Estate Faridabad	3000000
22	M/s Robindera Textlie Mills, 14/5, M.R. Faridabad	666000
23	M/s High Polymers Labs, Plot No. 5, Sector-25 Ballabgarh	1275000
24	M/s Siemen Laboratoies,15/11, Inderpuri, Gurgaon	165000
25	M/s rajdhani electric Pvt. Ltd., Plot no. 47, Setor-4 Faridabad	1700000
26	M/s Puri Foundary & Engg. Works, Sector-27-C. Indl. Plot No. 60, Amar Nagar, Faridabad	212000
27	M/s Associated Strips P. Ltd. Plot No. 81, Sector-6, Faridabad	275000
28	M/s Kapoor Lamp Sheds Co.1 DLF, I.E.M.R, Faridabad	384000
29	M/s Jasia Tyres P. Ltd., lot No. 6, I.D.C., Gurgaon	582000
30	M/s Vikas Forgings Pvt. Ltd., Plot	666000

	No, 173, Sector-24, Faridabad	
31	M/s Richstake Chemicals Pvt. Ltd., 25 Kailash apartments, Kailash Colony, new Delhi (Factory at Gurgaon)	170000
32	M/s Hada steel Products Ltd., M.R., Faridabad	548000
33	M/s Rattan Chand Harjas rai (Moulding) Pvt. Ltd., 54, I.A., Faridabad	200000
34	M/s Standard Malts Ltd.,Vill. Narsingpur, P.O. Khandsa	Withdrawn
35	M/s Shiva Inds. 70-D.L.F., I.E, Faridabad	Do
36	M/s Morinda Engg. works, 13/3, Mile stone, M.R. Faridabad	Do
37	M/s cryspal Index Plot No. 26, Sector -27 Faridabad	Do
38	M/s Standard Malts Ltd., 38/6, Milestone, National Highway no. 8, Gurgaon	Do
39	Ms/s Kataria Potteries, Daultabad Road, Gurgaon	Do
40	M/s Sai Parshanti Pvt. Ltd., 21st	Rejected

	K.M., M.R., Faridabad	
41	M/s Sikands Ltd., 61, Nit, Faridabad	Rejected
42	M/s Haryana Textile 8, Sadar Bazar, Gurgaon	Do
43	M/s Sundip drugs P.Ltd., 204, Saraswati Bhawan, 27, Nehra place, New Delhis(Factory at Faridabad)	Pending
44	M/s Sunita Suitings & Fabrics P. Ltd., D 1/55, Vasant Vihar, New Delhi (Factory at Faridabad)	Do
45	M/s Supreme Bone Mills, R-657 New Rajendra Nagar, New Delhi (Factory at Gurgaon)	Do
46	M/s Modern Auto rubber Products 8393, Roshan ara road, Delhi (Factory at Gurgaon)	Do
47	M/s J.J. Inds.,15/3, M.R., Faridabad	Do
48	M/s Vidyut Engg. & Technologies P.Ltd., 17, Gurgaon, I.E., Girgaon	Do
49	M/s Faridabad Manufacturing (Engg. Products) Pvt. Ltd., Plot No.	Do

	68, Sector-6, Faridabad	
50	M/s Mittal Pal Aggarwal 1/43, DLF, I.E, Faridabad	Dos
HISSAR		
1	M/s Vir Dal & Oil Mills, Rly, Road, Near Anaj Mandi, Tohana	22000
2	M/s Shanker Metal Inds. Sainipura, Hansi	250000
3	M/s Guruji production of indias, 2045, rampura Mohalla, Hissar	838000
4	M/s Doaba automobiles Engg. works Barwala Road, Hissar	97000
5	M/s Singhal Inds., 10-I.D.C. Hissar, Roshan	110000
6	M/s Jain Steels, Chandigarh Road, Tohana	432000
7	M/s indian Weaving Factory, Old Bus Stand, Hansi	88000
8	M/s M.P. Textile Inds. 8, I.A., Delhi road, Hissar	88000
9	M/s Haryana Bones & Fertilizer Inds. Fatehabad Road, Bhattu (Distt. Hissar)	152000

10	M/s Singal Cotton Ginning & Dall Inds., Ludas road, Hissars	Withdrawn
11	M/s Jain Plastic Inds., Kala Kendra Road, Near Prem Nagar, Hissar	Do
12	M/s Singh Chemicals, Hansi Road, Barwala	Rejected
13	M/s Ganga Cold Storage & Ice factorys, G.T. Road Fatehabad	Do
14	M/s Saunthalia Sugandhit Dhoop Factory, Vill. Gangwa	Pending
15	M/s Virjee Chemicals, Chandigarh Road, Tohana	Do
16	M/s Haryana Paper products C/o Jagjit Singh, H.No. 322, Ward No. IV, Hansi.	Do
17	M/s Gupta Stel & Potteries, Gupta bhawan, Rly. Road, Hissar	Pending
18	M/s Rajendra Inds., 12, Inds. Colony, Hissar	Do
19	M/s Kumar Inds., 44, Inds. Develoopment Colony, Hissar.	Do
JIND		

1	M/s Agarwal Cotton Ginning & Oil Factory, Railway Road, Kalayat	95000
2	M/s Kundan lal Jai Bhagwan, Railway Road, Kalayat	166000
3	M/s Jind Body Buliders, Rohtak Road, Jind	476000
4	M/s Universal Chemicals Industries, Julana Road, Jind	185000
5	M/s Aggarwal Plastic Udyog, Jind	77000
6	M/s Pragti Fertilizers, Jind Gohana Road, Jind	Pending
7	M/s M/s Pal Auto Moblie Engg. works, Old Hansi Road, Jind	Do
8	M/s laxmi Dal & General Mills C/o M/s Ram Sarup Subash Chand, Kalayat Mandi	Do
	KARNAL	
1	M/s Kishore spinning & Weaving Mills, G.t. Road, Panipat	358000
2	M/s Raghukul Taextile, 48, Rajguru Stret, College Road, Civil Lines, Ludhiana (Factory at	147000

	panipat)	
3	M/s Prince Handloom Inds. 351/7, Panipat	82500
4	M/s Parveen Handloom Inds. 383/7, Panipat	69000
5	M/s Jagdish Kumar Aggarwal, G.T. Road, Miran Ghati, Karnal	430000
6	M/s R.K. Woollen Mils, Unit No. II, I.A. Panipat	100000
7	M/sGogia Handloom Inds.,612, Ward No. 6, Khail bazar, panipat	110000
8	M/s Pritam Foundary & Steel Inds. Karnal	45000
9	M/s Krishana Textile Inds., Panipat	110000
10	M/s Adarsh Woollen Inds., Panipat	158000
11	M/s Kishore Spinning & Weaving Mills, G.T. Road, Panipat	112000
12	M/s Radha Textlie Inds., Shop No. 555, Ward No. 4, panipat	87000
13	M/s puranChnad Ashok Kumar Plot No. 41, Vijay Nagar, near Devi mandir, panipat	64000

14	M/s Kishore Suitings, G.T. Road, Panipat	835000
15	M/s Sky Lark Paints & Chemicals Indl. Estate, Nilokheri	20000
16	M/s Arora handloom Industries, H.no. 537-Ward No.7, Panipat	45000
17	M/s raj Hans Handloom Industries, House No. 948, Ward No. 11, Panipat	71000
18	M/s Jaginder Saw Mills H. No. 390, Ward No. 10, sanoli Roads, Panipat.	40000
19	M/s Chaudhri Textile, G.T. Road, Panipat	2000000
20	m/s Gulshan Handloom Industries, House No. 614, Ward No. 11, Panipat	Withdrawn
21	M/s Chanderlok Handloom Industries, Plot No. 5 , Near Mahavir Colony, Jatel Road, Panipat	Do
22	M/s Chanderlok Handloom Industries, Plot No. 5 B, Near Mahavir Colony, Jatel Road, Panipat	Pending

23	M/s Parkash Iron & Foundary & Engg. Works, Near Railway Crossing Hansi Road, Karnal	Do
24	M/s Neki Spinning & Woolleen Mills, C/o M/s Mussadi Lal neki Ram, Cloth Merchants, Safidon Mandi, (Factory at Panipat).	Do
25	M/s Variety Handloom Productss, Weavers Colony, Sanoli Road, Panipat	Pending
26	M/s Raju Handloom Indus., sanoli Road, Near Subzi Mandi, Panipat	Do
KURUSHETRA		
1	M/s Rajdhani Card Board Mills, Vill. & P.O. Mathana Ladwa Pipli Road	250000
2	M/s Jagdabey General Industries, 54, Partap Mandi, shahabad Markanda	650000
3	M/s MadanpurIce & Cold Storage, Madanpur, Shahabad, Markanda	455000
4	M/s Rabindra Cold Storage, ambala Hisar Road	300000
5	M/sSuresh Cotton Ginning & General Mills, Shergarh Road, near	Withdrawn

	Power House, Kaithal	
6	M/s B.B. Rice Mills, Chika	Pending
MOHINDERARH		
1	M/s Shree Durga Ice Factory, Kerelia Bazar, Mohindergarh	99000
2	M/s Darby Star Scraw Factory, Chiptwara, Rewari	72000
3	M/s Haryana Detergent Ltd. Dharuhera	3000000
4	M/s Haryana Pipe Manufacturing Industries, Ganduchaahir, Teh, Rewari	72000
5	M/s New India Metal Industries, Circular Road, rewari	49000
6	M/s Kumar Surgical Indus., V. &P.O. Gokal Garh Teh. Rewari	52000
7	M/s Rewari Metal (India Products) Prop. Enterprises, I. Civil Lines, Gurgaon (Factory at Rewari)	233000
8	M/s Narnaul Mills Board, Singhana Road, Narnaul	245000
9	M/s Everest Metals, Jhajjar Road, Rewari	Pending

10	M/s supreme Pipes, Railway Road, Narnaul	Do
ROHTAK		
1	M/s sangam Refractories, Modern Indus. Area Bahadurgarh	154000
2	M/s S.S. Thread Mills Bhadurgarh	53000
3	M/s Bharat Udyog Vill. Kassar Bhadurgarh	Withdrawn
4	M/s Vikas Refractories, Barha Narhi Road, Bhadurgarh	Withdrawn
5	M/s Lakshmi Precision Screws, Ltd. Hissar Road Rohtak	Do
6	M/s Ishwar Singh H.N. 162 Ward No./ 15, Jhajjar Road Rohtak.	Do
7	M/s Rajesh Paper Industries V.P.O. Madina	Pending
8	M/s lakshmi Precision Screws Ltd. Hissar Road Rohtak	Pending
9	M/s Haryana Textile, CHIO/B Inddl. Area, Bhadurgarh	Pending
SIRSA		
1	M/s Bharat Steel Industriess, Vill	182000

	Ram Nagria Ranuia Road, Sirsas	
2	M/s R.K. Inds. Vill. Bajekam, sirsa	419000
3	M/s Gupta Plastic Indus., Cinem Road, Kalanwali	80000
4	M/s Standard Surgicals C/o Bjoj raj Hari Chand Bhadra Bazar, Sirsa.	635000
5	M/s R. K. Cotton & Pressing Industry Mohar Road Ellenabad (Distt. Sirsa)	1000000
6	M/s Santok Singh Kalra & Sons, Subash Chowk, Sirsa.	Withdrawn
7	M/s Sarjit Cold Storage, Vill. Bajekan Teh. and District Sirsa.	Rejected
8	M/s Seth Mal Cotton Ginning Mills Ellanabad Distt. Sirsa.	Rejected
9	M/s B.G. Finance & Industries Ltd., Sirsa	Do
10	M/s Gurpesh Ugars P.Ltd., Gajja Singh nagar (Shakit Khera)	Pending
11	M/s Kiran Testiles C/o M/s Sirsa Woollen Dabwali Road Sirsa.	Pending
12	M/s Surindera Bros. Steel and agri. Industries. Opp. Bus Stand,	Do

	Mandi Dabwali.	
SONEPAT		
1	M/s Janta Ice Factory & Cold Storage	360000
2	M/s Saluja CementSpun Pipe Plot No. 11, murthal Industrial Estate, Sonepat.	137000
3	M/s Gopi Industrial Corporation Q-4, Industrial Estate, Murthal	175000
4	M/s Hindusthan Rolling & Wires Pvt. Ltd., Sonepat	119000
5	M/s Rubber Reclaim Co. of India Pvt. Ltd., 22/4, Mile Stone G.T. Road, Bahal Garh.	347000
6	M/s Kumari paints, Industrial Estate, Murthal	148000
7	M/s Kisan Cold Storage, Ice & General Mills, Khanna Colony, Delhi Road, Sonepat	230000
8	M/s Haryana Sports & Scientific Emporium, 4/335, Behind Gir, Mandi Sonepat	45000
9	M/s Indo Solex Ltd., Deepalpur Road, Bahalgarh	223000

10	Haryana Niwar Factory, Narala Road, Kundli	70000
11	M/s Property Electrical Indl. Pvt. Ltd., E-39, Industrial Area, Sonepat	162000
12	M/s Rubber Reclaim Co. of India (P) Ltd., Sonepat	1150000
13	M/s Kisan Cold Storage, Ice & General Mills, Sonepat	Withdrawn
14	M/s Varsha Foundry M-4, Industrial Atrea, Sonepat	Do
15	M/s Haryana Vester Udyog, 358 K.M. G.T. Road, Vill. Rasoi, P.O. Nathupur	Pending

HINDI

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand): Sir, I beg to lay on the Table the Haryana Development Authority Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 1 of 1977).

I also beg to lay on the Table-

1. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 2 of 1977).

2. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 3 of 1977).

3. The Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 4 of 1977).

4. The Haryana Urban Development and Regulations of Urban Areas (Haryana Amendment) Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 5 of 1977).

5. The 7th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1973-74. As required under section 31(2) of the warehousing Corporation Act, 1962.

6. The 8th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1974-75 as required under section 31(2) of the warehousing Corporation Act, 1962.

7. The Second Annual report of the Haryana State Minor Irrigation (Tube wells) Corporation Limited for the year 1971-72, as required under section 619(A) of the Companies act, 1956.

8. A copy of the following Notification of the Transport Department, Haryana, containing amendments in the Punjab Motor Vehicles rules, 1940, as required under section 133(3) of the Punjab Motor Vehicles Act, 1939:-

(i) Notification No. GSR-228/CA-4/39/S-24 &41 /Amd. (15)/76, dated the 21st October, 1976.

(ii) Notification No. GSR-229/CA-4/39/S-24/Amd. (16)/76, dated the 21st October, 1976.

(iii) Notification No. GSR-230/CA-4/39/S-68 /Amd. (17)/76, dated the 21st October, 1976.

(iv) Notification No. GSR-237/CA-4/39/S-70/Amd. (18)/76, dated the 21st October, 1976.

9. The Delimitation of Parliamentary Constituencies Order, 1976, as required under section 8(2) of the representation of the People Act, 1950.

10. The Development and Panchayat Department Notification No. GSR3/H.A.30/70/S.22/Amd.(10/77, dated the 5th January, 1977, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendments) Rules, 1977, as required under section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

11. The Education and language Department Notification No. 1132-Edu/Lg-77/4515, dated the 16th February, 1977, as required under section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969.

12. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1975, together with the memorandum explaining reasons for non-acceptance of the advice of the Haryana Pubic Service Commission, as required under article 323(3) of the Constitution in India.

Sir I beg to relay on the Table-

1. The political Department Haryana Notification No. GSR-163/HA3/75/S.8/76, dated the 2nd July, 1976, regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car)Rules, 1976, as required under section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

2. The Revenue Department Haryana Notification No. GSR.

10/HA.26/72/S.31/Amd.(1)/76, dated the 23 January, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (First amendment) rules,1976as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

3. The Revenue Department Haryana Notification No. GSR.

67/HA.26/72/S.31/Amd.(2)/76, dated the 5th April, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (First amendment) rules,1976as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

4. The Revenue Department Haryana Notification No. GSR.

183/HA.26/72/S.31/Amd.(3)/76, dated the 4th August, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings

(Third amendment) rules,1976as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

5. The Revenue Department Haryana Notification No. GSR.

222/HA.26/72/S.31/Amd.(4)/76, dated the 15th October, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Fourth amendment) rules,1976as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

6. The Excise and Taxation Department, Haryana Notification No. GSR 149/HA20/73/S.64/Amd.(1), 76, dated the 18th June, 1976, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1976, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

7. The Development and Panchayat Department Notification No. GSR24/H.A.30/70/S.22/Amd.(1) 76, dated the 27-2-1976, regarding the Haryana Cattle fairs (First amendment) rules, 1976, as required under section 22(3) of the Haryana Cattle fairs Act, 1970.

8. The Development and Panchayat Department Notification No. GSR147/P.A.3/61/S.115/Amd.(1) 76, dated the 11th June, 1976, regarding the Punjab Panchayat Samiti and Zila Parishad Non-Official members (Payment of Allowances (Haryana First Amendment) Rules, 1976, as required under section 115(4) of the Punjab Panchayat Samiti Act, 1961.

9. The Revenue Department Haryana Notification No. GSR. 121/HA.8/76/S.25/76, dated the 12th May, 1976, regarding the Haryana Relief of agricultural Indebtedness Rules, 1976, as required under section 25(3) of the Haryana Relief of agricultural Indebtedness Act 1976.

10. The Town and Country Planning Department Notification No. GSR. 107/HA.8/75/S.24/76, dated the 7th march, 1976, regarding the Haryana Urban Development and Regulations of Urban Areas Rules, 1976 as required under section 24(3) of the Haryana Urban Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

11. A copy each of the following notification issued under section 133(3) of the Motor Vehicle Act, 1939:-

(i)TransportDepartmentNotificationNo.G.S.R.190/C.A.4/39/S.68/Amd.(3)/75, dated 16-12-75.(

ii) Transport Department Notification No.G.S.R.108/C.A.4/39/SS/24 &

41/Amd.(4)/76, dated 7-5-76

(iii) Transport Department Notification No.G.S.R.109/C.A.4/39/SS/24 & 41/Amd.(6)/76, dated 7-5-76

(iv) Transport Department Notification No. G.S.R.110/ C.A.4/39/SS/24 &

41/Amd.(6)/76, dated 7-5-76

(v) Transport Department Notification No.G.S.R.111/C.A.4/39/SS/24 &

41/Amd.(7)/76, dated 7-5-76

(vi) Transport Department Notification No.G.S.R.112/C.A.4/39/SS/24 & 41/Amd.(8)/76, dated 7-5-76

(vii) Transport Department Notification No.G.S.R.113/C.A.4/39/SS/24 &

41/Amd.(9)/76, dated 7-5-76

(viii) Transport Department Notification No.G.S.R.114/C.A.4/39/SS/24& 41/Amd.(10)/76, dated 7-5-76

(ix) Transport Department Notification No. G.S.R.115/C.A.4/39/SS/24 &

41/Amd.(11)/76, dated 7-5-76

(x) Transport Department Notification No. G.S.R.116/ C.A.4/ 39/SS/24 & 41/Amd. (12)/76, dated 7-5-76.

41/Amd.(12)/76, dated 7-5-76

(xi) Transport Department Notification No. G.S.R.125 /C.A.4 /39/SS.63 & 68/Amd.(13)/76, dated 21-5-7

(xii)TransportDepartmentNotificationNo.G.S.R.113/ C.A.4/39/S.68/Amd.(14)/76, dated 28-5-76.

वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी कि त) का पे ा करना

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Third Installment) for the year 1976-77.

प्राक्कलन समिति का वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पर प्रतिवेदन पे ा करना

Shri Nihal Singh(Chairman, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates(Third Instalment) for the year 1976-77.

वर्श 1971–72 तथा 1972–73 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों का पे ा करना

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 1971-72.

I also bet to present the Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 1972-73.

नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव

Transport Minister(Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

That the discussion of Governor's Address be postponed in favour of Financial and other (date bound) Government Business and that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of Financial and other (date bound) Government Business and that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि इस तरीके से जल्दी करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि ऐसी जल्दी क्या है? गवर्नर एड्रैस पहले आया है तो उसके ऊपर पहले डिस्क ान हो जानी चाहिए। पंजाब का सै ान 30 को आ रहा है। वह भी गवर्नर एड्रैस डिस्क्स करेगें और बजट भी पास करेंगें.....

मुख्यमंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): वह तो सिर्फ वोट आन अकाउन्ट कर रहे है.....

चौधरी राम लाल वधवाः मेरी प्रार्थना यह है कि मैं इसको अपोज करता हूं, इसको पास न किया जाये।

Mr. Speaker: Question is---

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of Financial and other (date bound) Government Business and that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker.

The Motion was carried.

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, डे तो फिक्स कर दीजिये।

Mr. Speaker: That is my business. I will fix it.

वर्श 1977–78 का बजट पे ा करना

वित्त मन्त्री(श्री राम सरन चन्द मित्तल): महोदय,

मैं वर्श 1977–78 के बजट अनुमान इस गरिमामय सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

आर्थिक स्थिति

वर्श 1977–78 के बजट अनुमानों का विवेचन करने से पूर्व, मैै राज्य की आर्थिक स्थिति के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करना चाहूंगा।

वित्त वर्श 1975–76 में राज्य की अर्थ–व्यवस्था मे उल्लेखनीय सुधार हुआ। हसमें 15 प्रति ात अनुमानित विकास दर हुआ जोकि आज तक चालू पंचवर्शीय योजना के दौरान सब से अधिक है। 1975–76 में खाद्यान्न उत्पादन 50.38 लाख टन तक पहूंच गया और इस प्रकार वर्श 1974–75 में हुये उत्पादन के मुकाबले में उत्पादन में 50 प्रति ात से अधिक वृद्धि हुई खरीफ 1976 के दौरानधान का उत्पादन 7.72 लाख टन हो गया ओर इस प्रकार उत्पादन के पिडले सभी रिकार्ड मात हो गए।

राज्य में अच्छे वातावरण और श्रमिक गड़बड़ी से मुक्त स्थिति के कारण ओद्योगिक विकास लगातार होता रहा। जून, 1976 में छोटे पैमाने की 16700 इकाइयां थी जोकि नवम्बर,1976 के अन्त तक बढ़कर 18725 हो गई।

संगठित क्षेत्र में समुचे रूप में रोजगार 1974–75 में 3. 75 लाख से बढ़कर 1975–76 में 4.03 लाख हो गया और इस प्रकार एक ही वर्श में 28000 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

राज्य सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखने के लिये उत्पादक क्षेत्रों में खर्च को जारी रखा, प्र ाासनिक खर्च में बचत की और जनता को सस्ते तथा उचित मूल्य पर अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धि सुनि चत की। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में और सुधार किया गया और राज्य के देहाती और भाहरी क्षेत्रों में सस्ते

मूल्य की दूकानों का जाल बिछा कर गेहूं, आटे, चावल चीनी, मिट्टी के तेल इत्यादि जैसी वस्तुएं जनता को सप्लाई की गई। नियंत्रित मूल्य के कपड़े का सुव्यवस्थित ढंग से वितरण किया गया । आर्थिक द ाा में सुधार के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की राजस्व–प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिस से राज्य सरकार उत्पादक क्षेत्रों के लिये अधिक धन जुटाने के योग्य हो सकी है।

लेखे 1975–76

1975–76 के सं ाोधित अनुमानों के अनुसार वर्श के अन्त में (––)8.92 करोड़ रूपये के भोश की सम्भावना थी। महालेखाकार, हरियाणा द्वारा संकलित लेखों से पता चलता है कि वर्श के अन्त में (––) 12.97 करोड़ रूपये का भोश रहा। परन्तु वास्तव में वर्श 1975–76 का घाटा 17.27 करोड़ रूपये हुआ जिस में वर्श 1975–76 के वित्त वश्र के अन्त में बकाया अर्थोपाय पे ागियां भी भाामिल है। इस प्रकार वर्श 1975–76 के वास्तविक लेन–देन से उस वर्श के सं ाोधित अनुमानों से 8.35 करोड़ रूपये का अधिक घाटा रहा। यह घाटा मुख्यतः दो महत्त्वपूर्ण बातों का परिणाम था। पहली बात थी ब्याज की वसूलियों में 4.62 करोड़ रूपये की कमी। इस रा ि ा में 2.38 करोड़ रूपये राजस्थान सरकार से ब्यास लेखें की ब्याज–वसूलियों से सम्बन्द्ध है। वर्श के दौरान इन की वसूली राज्य सरकार के पूरे प्रयत्न करने पर भी नहीं हो सकी। इसके अलावा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त 1.94 करोड़ रूपये के ब्याज को ऋण के रूप में बदल दिया गया

था ताकि पानीपत ताप बिजलीघर के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये उपस्कर की बोर्ड द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड को अदायगी की जा सके। दूसरी बात थी (क) अन्य प्र ाासनों को पुलिस की सेवाएं दी जाने के कारण राज्य पुलिस विभाग की वसूलियों में 0.79 करोड़ रूपये की कमी, (ख) भारत सरकार द्वारा लागू की गई परिसम्पत्ति सीमा के कारण भाहरी सम्पदाओं में सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी अनि चय के अतिरिक्त अन्य अनेक करणों से भाहरी सम्पदा विभाग की आय में 2.83 करोड़ रूपये की कमी। इन बातों की और ध्यान न दिया जाये तो वर्श 1975–76 के लेखों में उस वर्श के सं ाोधित अनुमानों के मुकाबले में नि चत रूप से सुधार हुआ है। इस वृद्धि और योजनेतर खर्च पर कड़ा नियन्त्रण रखने के कारण राज्य सरकार वर्श 1975–76 के दौरान 108.35 करोड़ रूपये की बड़ी योजना के लिये धन जुटाने में समर्थ हो सकी है।

1976–77 के सं ाोधित अनुमान और 1977–78 के बजट अनुमान

चालू वर्श के बजट अनुमानों के सं ाोधन तथा वर्श 1977–78 के बजट अनुमानों के परिणामस्वरूप स्थिति इस प्रकार है–

		बजट अनुमान	सं ाोधित अनुमान	बजट अनुमान

		1976–77	1976–77	1977–78
1	प्रारम्भिक बकाया––	(रूपये करोडो में)		
	(क) लेखा–पुस्तकों के अनुसार	-8.92	-12.97	-5.58
	(ख) खजाना बिलों में निवे ा	5.94	5.94	5.94
2	राजस्व लेखा––			
	प्राप्तियां	236.36	277.47	294.05
	खर्च	202.82	217.35	238.91
	अधि ोश	+33.54	60.12	+55.14
3	पूंजीगत खर्च	34.55	67.16	63.95
4	लोक ऋण			
	(क) लिया गया ऋण	110.01	119.67	134.98
	(ख) वापिस किया गया ऋण	100.91	100.99	126.65
	निवल	+9.10	+18.68	+8.33

5	कर्जे तथा पे ागियां			
	(क) पे ागियां	41.92	37.16	41.15
	(ख) वसुलियां निवल	7.05 -34.87	8.09 -29.07	8.38 -32.77
6	अन्तर्राज्यीय संमजन	---	0.04	----
7	आकस्मिकता निधि(निवल)	---	---	---
8	अनिधिक ऋण(निवल)	+8.25	+8.05	+8.88
9	जमा तथा पे ागियां(निवल)	+11.15	+9.93	+12.85
10	प्रेशण(निवल)	---	+6.88	---
	वर्श का अन्तिम बकाया			
	(क) लेखा पुस्तकों के अनुसार	-16.30	-5.58	-17.10

	(ख) प्रतिभूतियों में निवे ा	5.94	5.94	5.94

वर्श 1976–77 के सं ाोधित अनुमानों के अनुसार चालू वर्श का घाटा 5.58 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि बजट अनुमान 1976–77 में प्रत्याि ात घाटा 16.30 करोड़ रूपये था। यह महत्वपूर्ण सुधार अत्यधिक खर्च(कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की दो किस्तों पर खर्च सहित) के बावजुद सम्भव हो सका है ओर यह मुख्य रूप से कृशि/औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण राजस्व–प्राप्तियों में वृद्धि होने, वर्श के दौरान अतिरिक्त साधन जुटाने, भारत सरकार द्वारा सिंचाई तथा बिजली की लक्ष्य पूर्ति हेतू वि ोश आर्थिक सहायता देने, तथा योजनेतर खर्च को सीमित रखने के लिए अपनाए गये किफायती उपायों और खर्च पर कड़ा नियन्त्रण रखने के कारण ही हो सका। सरकार के लिये अधिक योजना परिव्यय जुटाने हेतु चालू वित्त वर्श के दौरान अतिरिक्त साधन जुटाना आवश्यक था। यह योजना खर्च चालू पांचवी पंचवर्शीय योजना के आरम्भ से ही धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा था। वर्श 1973–74 में कुल योजना खर्च 85.90 करोड़ रूपये था जब कि यह खर्च बढ़ कर वर्श 1974–75 में 86.82 करोड़ रूपये और 1975–76 में 108.38 करोड़ रूपये हो गया। चालू वित्त वर्श में योजना व्यय 141.79 करोड़ रूपये तक बढ़ा दिया गया है।

वर्श के दौरान अतिरिक्त साधनों के जुटाए जाने से राज्य सरकार को लगभग 9.83 करोड़ रूपये की अतिरिक्त प्राप्तियां होने की सम्भावना है। केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा सामान्य वृद्धि के कारण लगभग 1.70 करोड़ रूपये बढ़ जाने की सम्भावना है। चालू वर्श के लिये सं ाोधित अनुमानों में केन्द्र सरकार से 17.59 करोड़ रूपये का अधिक सहायता अनुदान मिलने की प्रत्या ाा है। इस रा ि ा में अं ातः योजना तथा केन्द्रीय संचालित स्कीमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले सहायता अनुदान और अं ातः भारत सरकार द्वारा गेंहू तथा चावल की खरीद तथा निर्यात पर प्रोत्साहन बोनस में वृद्धि की रा ि ा भाामिल है। ब्याज–प्राप्तियां भी बजट अनुमान 1976–77 के मुकाबले सं ाोधित अनुमान 1976–77 में 3.12 करोड़ रूपये अधिक हो गई है। ब्याज–प्राप्तियों में यह वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है तथा यह वृद्धि मुख्यतः व्यास लेखे में राजस्थान सरकार से (2.72 करोड़ रूपये) ब्याज वसूल करने की राज्य सरकार की सफलता के कारण हुई है।

माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि सं ाोधित अनुमान 1976–77 में योजनेतर राजस्व व्यय सम्बन्ध वर्श के बजट अनुमानों से लगभग 10.00 करोड़ रूपये बढ़ गया है। व्यय में इस वृद्धि का वास्तविक कारण यह है कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1–3–1976 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की दो कि तों की स्वीकृति दी है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य कोश पर 3.00 करोड़

रूपये का अतिरिक्त भार पड़ा है। इसके अतिरिक्त यह वृद्धि मुख्यतः इन कारणों से हुई है – राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को तीव्र गति से मुकम्मल करने के लिए गत तथा चालू वित्त वर्श के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गस ऋणों के ब्याज की अदायगी, पैं ान तथा सेवा–निवृति लाभों की अधिक अदायगी, राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए उपबन्धित अतिरिक्त व्यय, ि ाक्षा विभाग द्वारा वि वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों की कार्यान्विति, चालू वर्श से गृह–कर तथा सम्पति कर को इक्ट्ठा कर देने के फलस्वरूप आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा एकत्रित गृहकर का स्थानीय निकायों को अदायगी करने के लिए वर्श 1976–77 के सं ाोधित अनुमानों में किया गया उपबन्ध। बजट अनुमान 1976–77 की अपेक्षा सं ाोधित अनुमान 1976–77 में योजनेतर व्यय में वृद्धि केवल उन्हीं भीशर्शों के अन्तर्गत की गई हैं, जहां यह अत्याव यक एवं अपरिहार्य थी।

चालू वित्त वर्श के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, भारत सरकार द्वारा वि ोश सहायतानुदान की व्यवस्था, कठोर व्यय–नियन्त्रण तथा विभिन्न बचत उपायों को लागू करने जैसे अपनाए गए अतिरिक्त साधनों से हम 111.15 करोड़ रूपये के बजट के मुकाबले में सं ाोधित अनुमानों में राज्य की वार्शिक योजना 1976–77 के लिए समुचे परिव्यय में 141.79 करोड़ रूपये तक की वृद्धि करने में सफल हो गए है। वर्श 1976–77 के

सं ाोधित अनुमानों में 16.10 करोड़ रूपये से 42.12 करोड़ रूपये की वृद्धि मुख्यतः'मुख्य एवं माध्यमिक सिंचाई परियोजनाएं' के अधिमान्यता क्षेत्र में हुई है। परिव्यय में वृद्धि अन्य बातों के साथ–साथ सतलुज यमुना योजक के निर्माण के लिए 16.00 करोड़ और जवाहर लाल नेहरू परियोजना के लिए 16.00 करोड़ रूपये का उपबन्ध करने के कारण है।

1977–78 के बजट अनुमान में 17.10 करोड़ रूपये का घाटा प्रत्याि ात है जिस में चालू वित वर्श का 5.58 करोड़ रूपये का सम्भावित घाटा भी भाामिल है। वर्श 1977–78 की वित्त नीति और वित्त व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को स्पश्ट करते समय मैं इसकों भी स्पश्ट करूंगा।

योजना परिव्यय

1976–77 के बजट में योजना परिव्यय अनंतिम रूप में 111.15 करोड़ रूपये रखा गया था। किन्तु अब यह मुख्यतः सिंचाई एवं बिजली परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित खर्च के कारण 1976–77 के संशोधित अनुमान में बढ़कर 141.79 करोड़ रूपये हो गया है।

योजना आयोग ने 1977–78 का योजना परिव्यय 148. 40 करोड़ रूपये नियत किया है। विकास की प्रगति को बनाये रखने तथा सिंचाई एवं बिजली की चालू परियोजनाओं को, जिन्हें राज्य की अर्थ–व्यवस्था के विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी

जाती है, भाीघ्र मुकम्मल करने के लिए इतना परिव्यय अनिवार्य है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन का वर्णन योजना स्कीमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में किया गया है।

बिजली

कृशि तथा उद्योग के , जो हमारी अर्थ–व्यवस्था के लिए परमाव यक है, विकास के लिए बिजली की उपलम्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्श 1977–78 के 148.40 करोड़ रूपये के राज्य योजना परिव्यय में से बिजली के लिए 54.02 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये है। बिजली उत्पादन स्कीमों को वि ोश महत्व दिया गया है। और 11.57 करोड़ रूपये की रा ि ा ब्यास यूनिट 1 तथा 2 के लिए और 21.00 करोड़ रूपये राज्य की अपनी बिजली उत्पादन स्कीमों के लिए जिन में फरीदाबाद तापीय संयंत्र, पानीपत तापीय संयंत्र और प ि चमी यमुना नहर जल विद्युत योजना भाामिल है, निर्धारित किये गये हैं फरीदाबाद में तापीय संयंत्र का 60 मैगावाट वाला दूसरा यूनिट अप्रैल, 1976 में चालू हुआ, जिससे कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 610 मैगावाट हो गई। देहर तथा पौंग बिजली संयंत्रों के चालू हो जाने से 1977–78 के अन्त तक राज्य की स्थापित क्षमता बढ कर 735 मैगावाट हो जाएगी। वर्श 1978–79 के दौरान देहर तथा पौंग में दो–दो और यूनिट चालू किये जाने की सम्भावना हैं । पानीपत तापीय संयंत्र का 110 मैगावाट का प्रथम यूनिट जून, 1978 में और दूसरा यूनिट मार्च, 1979 में चालू किया जाना प्रस्तावित है। इस के परिणामस्वरूप

1978–79 के अन्त तक स्थापित क्षमता 1072 मैगावाट हो जाएगी जिसमें 417.5 मैगावाट तापीय विद्युत, 652 मैगावाट जल–विद्युत और 2.5 डीजल विद्युत भाामिल है।

चालू वर्श के दौरान 12000 नलकूपों को बिजली देने का प्रस्ताव है। वर्श 1977–78 में 12000 और नलकूपों को बिजली देने का प्रस्ताव है।

हमने हिमाचल प्रदे ा सरकार से समझौता किया है कि हम हिमाचल प्रदे ा नाथपा–झकड़ी परियोजना के निर्माण में सहयोग देगें। नाथपा–झकड़ी परियोजना बिजली उत्पादन परियोजना है। इसकी क्षमता 1020 मैगावाट है। परिशण लाईनों के बिना इसकी अनुमानित लागत 271 करोड़ रूपये है। परियोजना–स्थल से हरियाणा में बिजली ले जाने के लिये परिशण प्रणाली की लागात 100.00 करोड़ रूपये होने की सम्भावना है। राज्य सरकार परिशण प्रणाली के सम्पूर्ण खर्च के अतिरिक्त परियोजना की पूंजीगत लागत का 80 प्रति ात खर्च वहन करेगी और उसका सदा के लिए उत्पादित बिजली के 80 प्रति ात पर एकमात्र अधिकार होगा। यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा निश्पादित की जाएगी, परन्तु इसमें हिमाचल प्रदे ा सरकार के अधिकारी भी पर्याप्त संख्या में सहयोग देगें। इस परियोजना पर कार्य, जो कि अभी आरम्भ किया जाना है, आठ वर्श के अन्दर पूर्ण किये जाने की सम्भावाना है। ब्यास परियोजना के, जो कि अब पूर्ण होने वाली है फालतु अमले को खपाने के अतिरिक्त यह

परियोजना राज्य में बिजली की आगामी आव यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी।

सिंचाई

निधियों के आंवटन में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जारी है।

चौथी योजना अवधि के दौरान मुख्य तथा मध्यम सिंचाई स्कीमेां पर 54.00 करोड़ रूपये खर्च किए गए। परिणामस्वरूप, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1966–67 में 32.75 लाख एकड़ से बढ़कर चौथी योजना अवधि के अन्त तक 41 लाख एकड़ हो गया।

चूंकि हमारा राज्य कृशि प्रधान राज्य है और यहां के 82 प्रति ात से भी अधिक लोग कृशि तथा इस से सम्बन्ध कार्यों में लगें हुये है, इसलिए माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होगें कि राज्य के लोगों की भलाई के लियें सिंचाई का विकास वि ोश महत्व रखता है।चालू पांचवी पंचवर्शीय योजना के दौरान, हमने राज्य में सिंचाई के विकास पर अधिक ध्यान दिया है। चालू पंचवर्शीय योजना के पहले वर्श अर्थात् 1974–75 के दौरान इन स्कीमों पर 10.54 करोड़ रूपये खर्च किये गये थे। वर्श 1975–76 में खर्च 17.83 करोड़ रूपये तक बढ़ गया। चालू वर्श में 42.12 करोड़ रूपये खर्च किये जाने की सम्भावना है, जबकि वर्श 1977–78 के लिये 47.34 करोड़ रूपये नियत किये गये है। इस

प्रकार, पंचवर्शीय योजना के पहले चार वर्शो के दौरान, राज्य में सिंचाई के विकास पर 117.83 करोड़ रूपये खर्च हो जाएंगें, अर्थात् चौथी योजना अवधि में इस क्षेत्र में किये गये खर्च से दुगुने से भी अधिक खर्च होगा।

पांचवी पंचवर्शीय योजना के दौरान किया जाने वाल खर्च मुख्यतः उठान सिंचाई स्कीमों तथा सतलुज यमुना योजक निर्माण कार्यो पर होगा। चार उठान सिंचाई स्कीमों में से जुई नहर परियोजना और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।, जबकि राज्य की सब से बडी उठान सिंचाई स्कीम अर्थात जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम का निर्माण कार्य पूरे जोर से चल रहा है। इन उठान सिंचाई स्कीमों का उद्दे य महेन्द्रगढ़, भिवानी और रोहतक जैसे राज्य के भुश्क क्षेत्रों की सिंचाई के अधीन लाना है। चालू पांचवी योजनावधि के दौरान 31 मार्च, 1976 के अन्त तक इन उठान सिंचाई स्कीमों पर कुल 20.34 करोड़ रूपये खर्च किये गये। चालू वित्त वर्श के दौरान इन स्कीमों पर 21.91 करोड़ रूपये खर्च होने की सम्भावना है, जबकि योजना आयोग द्वारा 1977–78 के लिये 15.08 करोड़ रूपये के आंवटन की सिफारि ा की गई है। इन उठान सिंचाई स्कीमों के पूरा हो जाने पर 14.32 लाख एकड़ का कुल क्षेत्र सिंचाई के अधीन आ जाएगा और 11.38 लाख एकड़ कृशि येाग्य सिंचित क्षेत्र होगा।

राज्य में सिंचाई के विकास के लिए सतलुज यमुना योजक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना से हरियाणा के हिस्से में आया रावी–व्यास का जल राज्य में लाया जाएगा और इस प्रकार इस से उठान सिंचाई स्कीमों को बारहमासी नहरें बनाने के साथ–साथ वर्तमान नहर प्रणाली में अधिक जल उपलब्ध हो सकेगा। भारत सरकार भूतपूर्व पंजाब राज्य के हिस्से में आने वाले 7.2 एम.ए.एफ. में से 3.5 एम.ए.एफ. हमारे राज्य के लिये पहले ही आवंटित कर चुकी है। सतलुज यमुना योजक पर निर्माण कार्य चालू वित्त वर्श के दौरान ही भुरू किया गया। इस परियोजना के लिये चालू वर्श के दौरान का आंवटन 16.00 करोड़ रूपये है, जबकि वित्त वर्श 1977–78 के लिये यह आंवटन 32.00 करोड़ रूपये का है। राज्य सरकार इस परियोजना को दो कार्य उपयुक्त ऋतुओं में पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

कृशि उत्पादन

कृशि उत्पादन की दृश्टि से वर्श 1975–76 असाधारण उपलब्धि का वर्श रहा है। राज्य में खाद्यान उत्पादन 50.38 लाख टन तक पहुंच गया है, जो कि हरियाणा राज्य के गठन के प चात् अब तक सबसे अधिक है। खरीफ 1976 के दौरान 7.72 लाख टन धान का रिकार्ड उत्पादन हुआ, जबकि ,खरीफ 1975 के दौरा 6.25 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। अतः चावल के उत्पादन में पिछले सारे रिकार्ड मात कर दिये गये और राज्य ने केन्द्रीय पूल में पहले ही 5.01 लाख टन चावल दे दिया है।

इस वर्श धान, गेहूं और चने के प्रमाणित बीजों के विरण में बहुत प्रगति हुई। धान के अधिक उपज वाले 8476 क्विंटल प्रमाणित बीज, गेहूं के अधिक उपज वाले 27608 क्विंटल प्रमाणित बीज और चने के 7240 क्विंटल बीज रियायती दरों पर वितरित किये गये, जिस के लिए राज्य ने 41 लाख रूपये सहायता अनुदान के रूप में खर्च किये। चालू वर्श के दौरान रासायनिक खादों की खपत भी पर्याप्त रूप से बढी़ और यह खपत खरीफ 1976 के लिए निर्धारित 35000टन के लक्ष्य के मुकाबले में 40339 टन तक तथा रबी 1975–76 के दौरान 72169 टन की पहले वाली अधिकतम खपत के मुकाबले 96806 टन तक पहुंच गई। राज्य सरकार ने रासायनिक खादों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये वर्श के दौरान 82.69 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी। रासायनिक खादों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त रात्य सरकार ने पौधों के सरंक्षण के लिए व्यापक उपाय अपनाये है। खरीफ 1976 के दौरान कपास के 1.04 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर हवाई छिड़काव किया गया , जबकि गत वर्श 0.28 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हवाई छिड़काव किया गया था। हवाई छिड़काव के अन्तर्गत लाये गये कपास क्षेत्र की प्रति ातता गत वर्श कपास क्षेत्र के मुकाबले मे लगभग 3.70 गुना अधिक है। कपास के अतिरिक्त, तिलहन के 16237 हैक्टेयर क्षेत्र में हवाई छिड़काव किया गया, जबकि गत वर्श 5000 हैक्टेयर में ही हवाई छिड़काव किया गया था।

हिसार तथा सिरसा जिलों के पांच खण्डों में कपास की एक वि व बैंक परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। सिरसा तथा नानियां के दो खण्डों को वर्श 1976 के दौरान परियोजना की कार्यान्विति के लिये लिया गया था। यह परियोजना आगामी तीन वर्शों में प्रतिवर्श एक खण्ड में कार्यान्वित की जानी हैं।

राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम भ्रारू किया है जोकि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उद्दे य भिवानी, महेन्द्रगढ़ जिलों और रोहतक जिला के सलहावास और नाहर खण्डों में कृशि तथा सम्बन्ध कार्यो के विकास के लिये आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के लिये भारत सरकार द्वारा चालू पंचवर्शीय योजना में 7.80 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों को निश्पादित तथा कार्यान्वित करने के लिए महेन्द्रगढ़, भिवानी और रोहतक जिलों में सोसायटी अधिनियम के अधीन सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एजेंसियां पंजीकृत की गई है। यह कार्यक्रम वित्त वर्श 1977–78 के लिये 2.00 करोड़ रूपये के मुकाबले में चालू वित्त वर्श के दौरान 1.50 करोड़ रूपये की कुल लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है।

विभाग भूमिगत जल विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और भूमिगत जल अनुसंधान संगठन ने, जिसे सुदृढ़ किया जा रहा है, इस क्षेत्र में बहुत ही प्रं ासनीय कार्य

किया हैं चालू वर्श के दौरान उथली लघु सिंचाइ यूनिटों की संख्या 217000 तक पहुंच जाने की सम्भावना है, जबकि गत वर्श की वास्तविक उपलब्धि 204736 यूनिटों की थी।

राज्य के छोटे किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की द ाा सुधारने की और लगातार ध्यान दिया जा रहा है। आजकल अम्बाला, गुड़गांव, भिवानी, जीन्द, रोहतक तथा हिसार में छोटे किसानों के विकास के लिए एजेंसियां कार्य कर रही है। छोटे किसानों के विकास संबंधी एंजेंयिों के अतिरिक्त राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा उठान सिंचाई स्कीमों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में छोटे किसानों और भुमिहीन श्रीमिकों के लिए भिवानी, रोहतक, नारनौल तथा गुड़गांव में डी.पी.ए.पी. एजेंसियां तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसियां बहुत अच्छा कार्य कर रही है।

राज्य में भूमि समतलन तथा भूमि सूधार कार्य जोरों से चल रहा है। चालू वर्श के दौरान हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम ने 4600 एकड़ भूमि का सुधार किया और 4933 एकड़ भूमि में भूमि समतलन कार्य किया। निगम ने वर्श 1977–78 के दौरान सुधार के लिए 27000 एकड़ के भूमि सुधार तथा 5700 एकड़ भूमि के समतलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को रियायती दरों पर जिप्सम दिया जा रहा है। छोटे किसानों को यह सहायतानुदान कुल लागत के 50 प्रति ात के हिसाब से दिया जाता है, जबकि अन्य किसानों को कुल लागत के 25 प्रति ात के हिसाब से दिया जाता है। वर्श 1977–78 के दौरान भी किसानों

को जिप्सम की सप्लाई रियायती दरों पर उसी प्रकार से की जाती रहेगी जैसे अब की जाती है।

राज्य ने वर्श 1977–78 में 51.00 लाख टन खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान नीति के अनुरूप विभिन्न स्कीमों के अधीन ट्रैक्टरों की खरीद तथा भूमि विकास के लिए संस्थागत ऋण दिए जाते रहेगें। वर्श 1977–78 के दौरान इन प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंको द्वारा किसानों को 20.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है। इस दि ाा में कृशि उद्योग निगम, हरियाणा कृशि विपणन बोर्ड, हरियाणा भाण्डागार निगम तथा हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है और राज्य की कृशि अर्थ–व्यवस्था के समुचित विकास में योगदान दे रहे है।

सहकारिता

प्रमुख रूप से कृशि पर आधारित राज्य में सहकारिता को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। राज्य में सहकारिता अभियान ने अत्यधिक प्रगति की है ओर इससे राज्य में हरित क्रान्ति के युग का सूत्रपात हुआ है। सहकारी समितियों ने अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि ऋणों की व्यवस्ाा करने और किसानों को कृशि उपस्कर और बीज आदि की व्यवस्था करने में पूरी सहायता की है। हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ (हैफेड) ने समस्त राजय में कृशि आधारित विधायन

यूनिटों की स्थापना कर के सराहनीय कार्य किया । इसने अपनी विपणन व्यवस्था के माध्यम से उनकी फालतू उपज को उचित मूल्य पर बेचने में किसानों की अत्यधिक सहायता की है। अब हैफेड हांसी में 25000 तकलियों वाली एक कताई मिल स्थापित कर रहा है। जल्दी ही इस मिल के चालू हो जाने की सम्भावना है।

हरियाणा राज्य सहकारी औद्योगिक संघ और हरियाणा हथकरधा ि ाखर बुनकर सहकारी समितियों जैसी ि ाखर औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को अपनी परियोजनाओं को तेज गति से कियान्वित करने के लिए स ाक्त बनाया गया है। औद्योगिक यूनिटों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री के लिए सारे राज्य में एम्पोरियम खोले गये है। उपभोक्ता स्टोरों के संगठन में सुधार लाया गया है ताकि इन्हे जनसाधारण को असव यक वस्तुंए वितरण करने में अधिक प्रभाव ाली बनाया जा सके।

हरियाणा दे ा में पहला राज्य है जिसमें 6189 कृशि उधार समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम 2168 यूनिटों में पुर्नगठित किया गया है। इन पुनर्गठित समितियों के लिए पूर्ण–कालिक मैनेजरों के पर्यवेक्षण के अधीन स्थानीय कार्यालयों की व्यवसाि की गई है। ये पुनर्गठित यूनिट देहाती क्षेत्रों में ''मिनी बैंक'' के तौर पर काम कर रहे है और लोगों के लिए कृशि तथा खपत उधार की व्यवस्था करते है।

करनाल और सोनीपत में 1250 मीटरी टन पीड़न क्षमता वाली दो चीनी मिलें स्थापित की गई है। हम भााहाबाद और पलवल में दो और सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने मे प्रयत्न ील है। इसके प चात् एक अन्य चीनी मिल की स्थापना जीन्द में की जाएगी।

पांचवी पंचवर्शीय योजना में राज्य में सहकारी विकास के लिए पहले 9.80 लाख रूपये के खर्च की व्यवस्था की गई थी। अब इसे बढ़ा कर 12.05 करोड़ रूपये कर दिया गया है। राज्य में 30—06—1976 को समाप्त होने वाले द ाक के दौरान सहकारिता आंदोलन ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इस प्रगति का अन्दाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वित्त पर्श 1977—78 के अन्त तक कृशि आधारित परिवारों की संख्या 49.8 प्रति ात से बढ़कर 70 प्रति ात उधान लेने वाले सदस्यों की संख्या 57 प्रति ात से बढ़कर 70 प्रति ात, अल्पावधि पे ागियां 43.55 करोड़ रूपये से बढ़कर 60.00 करोड़ रूपये, दीर्घावधि पे ागियां 13.29 करोड़ रूपये बढ़कर 20 करोड़ हो जाने की सम्भावना है। इस के अतिरिक्त वित्त वर्श 1977—78 के अन्त तक सहकारी समितियों द्वारा बेची जाने वाली कृशि उपज 40.53 करोड़ रूपये से बढ़कर 55 करोड़ रूपये हो जाने की सम्भावना है और उपभोक्ता स्टारों की परचून बिक्री 10.69 करोड़ रूपये से बढ़कर 12 करोड़ रूपये हो जाने की आ ाा है।

प ाुपालन

राज्य प ुधन से सम्पन्न है और इस में प ुओं की सुप्रसिद्ध नसलें उत्पन्न होती है। हमने न केवल हरियाणा की अमान्यता प्राप्त प ु नसलों तथा मुर्राह भैंसों के चयनात्मक प्रजनन द्वारा उनकी सुरक्षा एवं सुधार का प्रयत्न किया है, अपितु दे ी प ुओं को संकर प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा सुधारने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया है। करनाल, गुड़गांव, अम्बाला, जीन्द, कुरूक्षेत्र तथा भिवानी जिलों में बड़ी सघन प ुधन विकास परियोजनाएं चलाई गई है। जिला अम्बाला में जगाधरी में एक जरसी संकर प्रजनन केन्द्र कार्य कर रहा है, इस संस्थान में छः कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 24 उपकेन्द्र है। डैनमार्क बैंक की सहायता से गुड़गांव में प्र ीतिि वीर्य बैंक (फ्रोजन सीमन बैंक) स्थापित किया गया है।

मुर्गी पालन विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त सफलता मिली है। अम्बाला में राजकीय मुर्गी

पालन फार्म को आध्रुनिक बनाया जा रहा हैं तथा मुर्गीयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राई में एक और मुर्गी पालन फार्म स्थापित किया जा रहा है। एस.एफ.डी.ए/एम.एफ.ए.एल. एजेंसीं, अम्बाला के अधीन मुर्गी पालने वालों को, अम्बाला के मुर्गी पालन फार्म से प्रति वर्श अंडा देने वाली 8000 मुर्गियों के सप्लाई किये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य में भेड़पालन में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। बिचौलियों द्वारा भाोशण को समाप्त करने के विचार से लोहारू(भिवानी) में ऊन कोटिकरण तथा विपणन केन्द्र द्वारा भेड़ पालने वालों से कच्चा ऊन सीधे ही खरीदा जाता है। ऊन केन्द्रों पर खरीदी जाती है। इन केन्द्रों में भेड़ पालने वाले आसानी से आ जा सकते है। वित्त वर्श 1977–78 के दौरान भेड़ पालकों से ऊन, खरीदने के लिये 20 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

हिसार में भेड़ पालन फार्म प्रजनन कार्य के लिये बढ़िया नस्ल के मेढे सप्लाई कर रहा है। चालू वित्त वर्श के दौरान एक भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्र चालू करने का प्रस्ताव राज्य में और अधिक प्रजनन सेवाएं तथा स्वास्थ्य सुविधांए उपलब्ध कराने के लिये इसी प्रकार के 25 केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे है।

राज्य में प ुधन को स्वस्थ रखने के लिये लगभग 200 प ु अस्पताल तथा 164 प ु चिकित्सा औशधालय वाला रोग नियन्त्रक सुगठित संगठन है, जिसमें 20 प ु अस्पताल तथा 20 प ु औशधालय चालू वर्श के दौरान स्थापित किये गये है। चालू वित्त वर्श के दौरान एक चौकसी यूनिट तथा एक पड़ताल चौकी बनाई गई है। वर्श 1977–78 के दौरान एक अन्य पड़ताल चौकी बनाई जाएगी। हरियाणा प ु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान, हिसार राज्य की आव यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त निकटस्थ राजयों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। यह संस्थान उत्तर भारत में एक प्रमुख जैविक उत्पादन केन्द्र है।

भारत सरकार तथा व्यापारिक बैंकों से उपलब्ध वित्तीय सहायता से छोटे सीमांत किसानों, भूमिहीन कृशि मजदूरों के लाभ के लिये वर्श 1975–76 के दौरान दोगली बछड़ी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन और ाोड़ पालन की एक परियोजना चलाई गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुर्गी पालन, सुअर पालन तथा भेड़ पालन, इकाइयों पर रियायती पूंजीगत निवे ा के अतिरिक्त दोगली बछड़ियों के पालन के लिये संतुलित आहार की व्यवस्था है। वर्श 1977–78 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृशि मजदूरों के लिये 94.90 लाख रूपये की रियायत देने का प्रस्ताव किया गया है।

डेरी विकास तथा दूध सप्लाई

अधिक दूध देने वाले प ाुओं, अच्छी भूमि तथा परिश्रमी किसान वर्ग के कारण हरियाणा में डेरी विकास की अच्छी सम्भावनांए है। 110 ग्राम दूध प्रति प ाु की अखिल भारतीय औसत के मुकाबले में हरियाणा में दूध देने की प्रति प ाु औसत 500 ग्राम से अधिक है। इस समय ने केवल दूध के उत्पादन में वृद्धि करना ही परम आव यक है, अपितु सम्पूर्ण एवं उत्तम दूध का उत्पादन भी परम आव यक है। फालतू दूध को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने के उद्दे य से अधिक दूध वाले क्षेत्रों में दुग्ध केन्द्रों (मिल्क पाकिट) का पता लगाने की आव यकता है। तदनुसार सरकार ने दुग्ध आयुक्त के स्वतन्त्र कार्यभार के अधीन एक अलग डेरी विकास विभाग की स्थापना की है जो राज्य में दूध

वाले क्षेत्रों में दुग्ध केंन्द्रो के लिये परियोजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करेगा और डेरी विकास योजनाएं भाुरू करेगा।

वैयक्तिक प्रयास को बढ़ावा देने के लिये गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिये सहकारी/वाणिज्यिक बैकों से 7.22 करोड़ रूपये के कर्जे लेकर उनकी वित्तीय सहायता की गई है।

हरियाणा डेरी विकास निगम, जीन्द, भिवानी, अम्बाला तथा रोहतक मं पहले ही दुग्ध संयंत्रों को मुकम्मल तथा चालू कर चुका है। फरीदाबाद में एक अन्य दुग्ध संयंत्र की स्थापना तीव्र गति से की जा रही है। कुछ एक दूध प्र ातिक केन्द्र भी खोले जा रहे है। वर्श 1976–77 के लिये निगम के समूचे कार्यक्रम का परिव्यय 87 लाख रूपये का है, जिसमें से 40 लाख रूपये की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। वर्श 1977–78 के परिकल्पित कार्यक्रमों के लिये 114 लाख रूपये की रा ि ा अपेक्षित है। निगम ने अपनी विपणन भााखा का सुधार किया है और इसने सुरक्षा सेवाओं को 1200 टन मीठा संघनित दूघ सप्लाई करने के वचन को सफलतापूर्वक निभाया है।

वन

राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 3.24 प्रति ात क्षेत्र वनों के अन्तर्गत है। अतः सड़कों, नहरों, रेलवे लाईनों, सरकारी भुमियों, मरूस्थल तथा पहाड़ी क्षेत्रों के साथ–साथ पट्टियों पर सघन वनरोपण का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान के

समीपवर्ती इलाकों में कृशि उत्पादन में स्थायित्व लाने तथा उस राज्य से मरूस्थल के खतरे का सामना करने के लिये भूमि संरक्षण तथा वृक्षारोपण हेतू वि ोश प्रयत्न किये गए है। वसनों का विकास राज्य की अर्थ व्यवस्था में भी सहायक होगा क्योंकि अनेक उद्योग वनों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर निर्भर करते है। चालू पंचवर्शीय योजना के प्रथम तथा द्वितीय वर्श में, राज्य सरकार ने 43.88 लाख रूपये तथा 48.60 लाख रूपये क्रम ाः वनारोपण तथा भूमि संरक्षण कार्यो के लिए खर्च किये है। चालू वित्त वर्श में इस उद्दे य के लिये उपबंधित रा ि ा को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है और अब यह 124.06 लाख रूपये तक पहूंच गई है। इस में से चालू वित्त वर्श के दौरान 163 लाख पौधे लगाने पर 69 लाख रूपये खर्च किये जाएंगे।

वर्श 1977–78 में वृक्षारोपण तथा भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यो को जारी रखने के लिये 206.98 लाख रूपये आवंटित किये गये है।

मछली पालन

राज्य में मछली पालन के लिये उपलब्ध जलस्त्रोत सीमित होने के कारण सरकार ने उत्तम किस्म की मछली के उत्पादन तथा इस उद्दे य के लिये जला ायों में सुधार करने पर जोर दिया है। चालू वर्श के दौरान 155000 मी0 टन मछली उत्पादन करने का लक्ष्य है, जिसे प्राप्त कर लिये जाने की

सम्भावना है। चालू वित्त वर्श के दौरान सात मछली ''पोना फार्म'' के अतिरिक्त हमने एक और मछली ''पोना फार्म'' की स्थापना करने तथा 5 हैक्टैयर जलक्षेत्र में मछली पालन जला ाय बनाने का प्रस्ताव किया है।

11.00 बजे– दे ाीय मछली पालन के व्यापक विकास के लिये करनाल में एक मछली पालन विकास एंजेसीं स्थापित की गई हैं नवम्बर, 1976 के अन्त तक अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों के 35 उम्मीदवारों को मछली पालन का प्र ि ाक्षण दिया गया। वर्श 1977 के अन्त तक 50 परिवारों के लिये मछली पालन द्वारा आजीविका कमाने के लिये पूर्णकालिक अवसरों की व्यवस्था करने की सम्भावना है।

उद्योग

चालू वर्श के दौरान औद्योगिक वातावरण बहुत ही भाांतिपूर्ण रहा है तथा आव यक कच्चे माल और बिजली की सप्लाई स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में और उन्नति हुई है तथा औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नए औद्योगिक यूनिट स्थापित किये गये है। लघु उद्योग क्षेत्र में 733 यूनिटों को नियमित आधार पर तथा 322 यूनिटों को अस्थायी आधार पर पंजीकृत किया गया है जिस से 1976 के अन्त तक राज्य में पंजीकृत लघु युनिटों की संख्या बढ़कर 18725 हो गई है। राजय में 65.50

करोड़ रूपये के निवे ा से 15000 व्यक्तियों को रोजगार की क्षमता वाले वृहत तथा मध्यम औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा 36 औद्योगिक लाइसेंस तथा 28 आ ाय–पत्र जारी किये गये।

जीन्द में एक औद्योगिक विकास कालोनी की स्थापना करने का प्रस्ताव है जहां इस उद्दे य के लिये 25 एकड़ भूमि अभिगृहीत की गई है। बहादुरगढ़ में एक नए औद्योगिक केन्द्र का ि ालान्यास किया गयाहै। इस केन्द्र में प्रथम चरण में लगभग (थम्पिग) 2600 प्लाटों का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार ने धारूहेड़ा में सिंथैटिक डिट्रजैंट के विनिर्माण के लिये एक यूनिट की स्थापना की हैं। धारूहेड़ा के स्थान पर गैर–सरकारी क्षेत्र में एक प्रतिश्ठापूर्ण कागज–परियोजना की भी स्थापना की जा रही है। गुड़गांव में गैर–सरकारी क्षेत्र में एक कलाई घड़ी परियोजना की स्थापना की जा रही है। इन परियोजनाओं में लगभग 3000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा।

राज्य में कारखानों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की क्वालिटी की और भी ध्यान दिया जा रहा है। गुड़गांव में इलैक्ट्रानिक्स के लिये एक 'परीक्षण विकास केन्द्र' के अतिरिक्त बहादुरगढ़ तथा हिसर में इंजीनियरी सामान के लिए दो नए गुण अंकन केन्द्र स्थापित किये गये है।

राज्य में हथकरघा उद्योग विकास के लिये बहुत सी स्कीमें बनाई गई है। इनमें उचित दरों पर हथकरघा उद्योग को विशिष्ट माल की सप्लाई, कमजोर उद्यमकर्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण–सुविधायें, पानीपत तथा भिवानी में बुनकरों की बस्तियों की स्थापना तथा भिवानी में सघन विकास परियोजना की स्थापना भी शामिल है। राज्य में हथरकघा उद्योग के विकास के लिये बनाये गये कार्यक्रम की प्रभावशाली तथा तीव्र कार्यान्विति के लिए राजय सरकार ने हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगमों की स्थापना की है। पानीपत परियोजना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और भिवान परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

सड़कें

कृशि तथा औद्योगिक उन्नति और अकाल तथा बाढ़ आदि जैसी आपातिक स्थिति का सामना करने के लिए सड़को का जाल बिछाना आवश्यक है। राज्य में सड़को के जाल विशेशतया ग्राम योजक सड़कें बिछाने में उल्लेखनीय उन्नति की उपलब्धि के विशय में माननीय सदस्य भली भांति परिचित है। हरियाणा बनने के समय, राज्य में पक्की सड़को की लम्बाई 5100 किलोमीटर थी तथा केवल 1386 गांव सड़को से जुड़े हुये थे। वर्श 1975–76 के अन्त तक, पक्की सड़को की लम्बाई बढ़कर 14930 किलोमीटर तक हो गई थी तथा पक्की सड़को से जोड़े गए गांवो की संख्या बढ़कर 4890 हो गई थी। चालू वित्त वर्श के दौरान 550

किलोमीटर सड़को को पक्का बनाए जाने तथा 250 गांवों को पक्की सड़को से जोड़े जाने की सम्भावना है। चालू वित्त वर्श के अन्त तक बरसाती जल तथा सिंचाई जल के कास जलनिकास के लिए 1200 पुलियों के भी मुकम्मिल हो जाने की सम्भावना है।

सड़क–तल के सुधार की और वि ोश ध्यान दिया जा रहा है। 'कै ाप्रोग्राम' के दौरान, जब कि अधिकतर ध्यान सड़को को पक्की बनाने की और दिया जा रहा था, इक्ट्ठे हुए समुचे बैकलांग को हटाने के लिये चालू वित्त वर्श के दौरान 4000 कि0मी0 सड़को के तल को सुधारा जाएगा। यमुनानगर में उपरिगामी पुल के निर्माण का कार्य पूरे जोरों पर है तथा इसे चालू वित्त वर्श में यातायात के लिए खोल दिये जाने की आ ाा है।

राज्य में भारी वर्शा के कारण बहुत सी सड़को को भारी नुक्सान पहुंचा। यह अत्यन्त सन्तोश का विशय है कि विभाग ने इस टूट–फूट की मरम्मत के सम्बन्ध में तुरंत कार्यवाही की और भारी कठिनाईयों के होते हुए भी इन सड़को पर सुगम यातायात की व्यवस्था की।

परिवहन

राज्य परिवहन अपनी वि वसनीय, नियमित तथा सुविधाजनक सेवा के लिये प्रसिद्ध है (थम्पिंग)। इस के पास 1987 बसें है जो चालू वित्त वर्श के अन्त तक बढ़कर 2100 हो जाने की

सम्भावना है। वर्श 1977–78 के दौरान 200 नई बसें खरीद कर इन की संख्या में और वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्श 1977–78 के दौरान 190 पुरानी बसों को बदलने का प्रस्ताव है।

राज्य परिवहन 5.11 लाख यात्रियों को दैनिक सेवा प्रदान करता है और प्रतिदिन 4.40 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अम्बाला भाहर, पानीपत, कैथल, भिवानी, रिवाड़ी तथा तो ाम जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के बस अड्डों पर यात्रियों के लिये अब आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था है। हांसी में नया बस अड्डा निर्माणाधीन है और सोनीपत, यमुनानगर, तथा टोहाना, में बस अड्डौं के निर्माण का कार्य भुरू कर दिया गया है। चालू वित्त वर्श के दौरान ीवानी, जीन्द, तथा कैथल में वर्क ाप भवन मुकम्मिल कर दिये जाने की सम्भावना है।

यात्रियों को सीधी यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए पडो़सी राज्यों के साथ किये गये अन्तर्राज्यीय नये करारनामों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। अत्यधिक यातायात के समय तथा मेला अवसरों के दौरान वि ोश यातायात सेवा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त विभिन्न मार्गों पर अब एक्सप्रैस सेवाएं प्रदान की जा रही है। 4 नई वातानुकूलित बसों के जल्दी ही चलाये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य परिवहन सेवाओं के वास्ते वर्श 1977–78 के लिये 5.30 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है। जबकि चालू वित्त वर्श के लिये 4.90 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई।

पर्यटन

हरियाणा पर्यटन दे ा भर में अपने पर्यटन केन्द्रों तथा सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हो गया है (थम्पिग)। यह अब पराम र्ा सेवाएं भी प्रदान कर रहा है और इसे दे ा भर में आधुनिक पर्यटन केन्द्रों की येाजना, विकास, निर्माण तथा प्रारम्भ करने के लिए संविदायें दी गई है। हरियाणा पर्यटन निगम को उत्तर प्रदे ा सरकार द्वारा उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लिये कई संविदायें पहले ही दी जा चुकी है।

चालू पंचवर्शीय योजना के पहले दो वर्शों में अपने विभिन्न कार्यकलापों के लिये विभाग द्वारा 1.59 करोड़ रूपये का खर्च किया गया था। चालू वित्त वर्श के दौरान 0.78 करोड़ रूपये की रा ि ा खर्च किये जाने की सम्भावना है जब कि वर्श 1977–78 के दौरान 0.65 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है ताकि यह नई स्कीमों को चालू करने ओर वर्तमान पर्यटन केन्द्रों में और सुविधायें प्रदान कर सकें। बढ़खल झील पर ड्राइव–इन–सिनेमा, कैम्पर, हट्स, ओपन ऐयर थियेटर का निर्माण, सूरज–कुण्ड पर डीयर पार्क की स्थापना, पिंजौर के यादविन्द्रा बाग में अतिरिक्त

स्थान की व्यवस्था, वर्श 1977–78 की कुछ नई स्कीमें है। हथनी कुण्ड, ताजेवाला तथा सुलतानपुर के लिये वन्य–जीव– ारण–स्थलों की भी योजना बनाई जा रही है।

ि ाक्षा

माननीय सदस्य ि ाक्षा के क्षेत्र में गुण एवम् मात्रा की दृश्टि से राज्य द्वारा की गई सर्वतोमुखी प्रगति की सराहना करेगें। चौथी योजना अवधि के दौरान 800 नये प्राइमरी स्कूल खोले गये, 279 प्राइमरी स्कुलों का दर्जा बढ़ाकर मिडल स्तर तक कर दिया गया, 277 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया गया जबकि लक्ष्य कम ाः 250, 150 तथा 60 का था। व्यापक प्राइमरी ि ाक्षा के उद्दे य को प्राप्त करने के लिए व्यापक नामांकन अभियान चलाया गया। चालू वर्श के दौरान 6–11 आयु वर्ग के लगभग 84000 और बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में दाखिल किया जायेगा। जिस से दाखिले की प्रति ातता बढ़कर 75 प्रति ात तक हो जायेगी। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को 1.50 किलोमीटर की दूरी के अन्दर–अन्दर प्राइमरी ि ाक्षा की सुविधा प्राप्त हो गई है। ऐसे गांवों में प्राइमरी स्कूलों की भााखायें खोली जा रही हैं, जंहा इस समय कोई भी स्कुल नहीं है। स्कूल ि ाक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये सभी वर्गों के अध्यापकों के लिये सेवा काल में प्रि ाक्षण के बृहत् कार्यकम का आयोजन किया गया और इसे बड़ी सावधानी से जारी रखा जा रहा है।

रोहतक में नये वि वविद्यालय ने जो मुख्यतः जीव विज्ञानों के अनुसन्धान तथा ि ाक्षण के लिए है अपना काम आरम्भ कर दिया है और सभी 12 महाविद्यालय, जो वि वविद्यालय से 16 किलोमीटर के घेरे में आते हैं, इससे सम्बन्ध कर दिये गये है। चालू वित्त वर्श में इस वि वविद्यालय के लिए 1.50 करोड़ रूपये का आंबटन किया गया है।

चालू वर्श के दौरान राज्य में तीन गैर सरकारी तथा एक सरकारी महाविद्यालय खोले गये है।

सरकार ने हरियाणा में स्कूल ि ाक्षा के अखिल भारतीय प्रणाली के अनुसार 10+2 प्रणाली की कमिक रूप से भुरू करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार अनौपचारिक ि ाक्षा पद्धति के अधीन अि ाक्षित किसानों, अर्ध–ि ाक्षित युवकों एवं समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहती हैं। यह ि ाक्षा पद्धति 6–11, 14–17 तथा 15–25 आयु वर्ग की सभी श्रेणियों के एि सफल सिद्ध हुई है। यह कार्यकम उत्साहपूर्ण जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

कालेज–युवकों को सामुदायिक जीवन से अवगत करवाया जा रहा है। उन्हें एन0एस0 प्रणाली द्वारा पिछड़े एवं दलित लोगों की सहायता करने की प्रेरणा दी जा रही है। वर्श 1977–78 के अन्त तक राश्ट्रीय सेवा स्कीम के स्वयं–सेवकों की

संख्या 8000 से बढ़ कर 10000 तक हो जाने की सम्भावना है। इस स्कीम के अन्तर्गत ''अकाल दूर करने के लिए युवक अभियान'' और ''गन्दगी तथा रोग दूर करने के लिये युवक अभियान'' दो वि ोश कार्यक्रम आरम्भ किये गये है।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 से 11 तक की श्रेणियों के लिए सभी राश्ट्रीयकृत पुस्तकों के मूल्यों में 10 प्रति ात की कमी की गई है। कुछ मामलों में कालेज स्तर की कुछ पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में भी 20 से 40 प्रति ात तक की कमी कर दी गई है। बुक–बैंकों की स्थापना की गई है और इन बुक बैंकों में पुस्तकौं की संख्या बढ़ाने के लिए वर्श 1977–78 के बजट में 9.50 लाख रूपये की रा ि ा का उपबन्ध किया गया है। स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को , भौक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थीयों के लिए बनाए गए स्टारों द्वारा नियंत्रित मूल्यों पर कापियां सप्लाई की जाती है।

खेल कूद

युवकों के व्यक्तित्व के विकास तथा उन में अनु ाासन एवं सहन ाीलता की भावना का विकास करने में खेलों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राश्ट्रीय चरित्र निर्माण में भी इस का योगदान है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने खेलकूद विभाग के माध्यम से अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये है जिन पर वित्त वर्श 1977–78 के दौरान 0.96 करोड़ रूपये खर्च किये जायेगें।

इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था, स्टेडियमों का निर्माण, टूर्नामैंटों का आयोजन तथा ग्रामीण खेलकूद केन्द्र खोलना आदि और राज्य के विभिन्न खेलकूद संगठनों को वित्तीय सहायता देना शामिल है (थम्पिग)। पात्र पुरूश खिलाड़ियों/महिला–खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां दी जाती है तथा राश्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला और अन्य संस्थानों में दाखिला लेने वाले हरियाणवी पुरूश खिलाड़ियों/महिला–खिलाड़ियों को नियमित रूप से वजीफे दिये जाते है। मोती लाल नेहरू खेलकूद स्कूल, राई तथा इसके जूनियर विंग कमला नेहरू स्कूल को स्थापित करना विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अपनी ही किस्म की एक बेजोड़ संस्था है जो युवक और युवतियों को उनके सर्वांगीण सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये अवसर प्रदान करती है। विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण पर विशेश जोर दिया जाता है ताकि खिलाड़ी राश्ट्रीय और अन्तर्राश्ट्रीय मुकाबलों में सर्वोत्कृश्ट रहें। समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए तथा 30 प्रतिशत सीटें सशस्त्र सेना के कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है। संस्था में 80 प्रतिशत सीटों पर उन बच्चों को दाखिला दिया जाता है जिन के माता–पिता संरक्षक हरियाणा निवासी है।

स्वास्थ्य

राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा–सुविधाओं सुधार लाने और उन्हें वि ोशकर देहाती इलाकों में उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। पंचवर्शीय योजना के लिए निर्धारित 12.35 करोड़ रूपये के परिव्यय के मुकाबले में हम चालू वित्त वर्श के अन्त तक 7.06 करोड़ रूपये खर्च करने की आ ाा करते है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं जुटाने और उन्हें सुधारने के लिए वर्श 1977–78 के लिए 2.85 करोड़ रूपये की रा ि ा नियत की गई है। चालू वर्श के दौरान देहाती क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप–केन्द्रों के माध्यम से अतिरिक्त दवाइयां सप्लाई करने के लिए 20.56 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की जा रही हे ताकि ''न्यूनतम आव यकता कार्यक्रम'' में नियत किया गया 12000 रूपये प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 2000 रूपये प्रति उप–केन्द्र का वार्शिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस लक्ष्य को वर्श 1977–78 के दौरान बरकरार रखा जायेगा और यदि संभव हुआ तो इसे बढ़ाया भी जायेगा।

वर्श के दौरान 6.50 करोड़ रूपये की कुल लागत से 20 अस्पतालों, 11 सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 8 औशधालयों का निर्माणकार्य हाथ में लिया गया है। भिवानी, पलवल, जगाधरी, सोनीपत, और हांसी में असप्तालों के लिए भवन बनाने और कुरूक्षेत्र में रिहाय ाी क्वार्टर बनाने के लिए वर्श 1977–78 के लिए 1.39 करोड़ रूपये की रा ि ा नियत की गई है। वर्श

1977–78 के दौरान, 5 आर्युवैदिक औशधालयों के अलावा 10 नये औशधालय खोलने का प्रस्ताव है।

जन स्वास्थ्य तथा जल सप्लाई

जब से यह राज्य बना है सरकार राज्य के अधिकां ा भागों में स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की कमी को बहुत महसूस कर रही है। चौथी पंचवर्शीय योजना के आरम्भ में राश्ट्रीय जल–सप्लाई एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 257 गांवों में पीने के पानी की सप्लाई, 40 नगरों में आंि ाक जल सप्लाई और 16 नगरों में छिटपुट मल–निकास सुविधाएं प्रदान की गई। चौथी पंचवर्शीय योजना के अन्त तक अर्थात् 31–3–1974 तक 21.89 करोड़ रूपये की कुल लागत से 713 गांवों में पीने के पानी की सुविधांए, 63 नगरों में आंि ाक जल सप्लाई और 24 नगरों में छिटपुट मल–निकास सुविधाएं प्रदान की जा चुकी थी। पांचवी पंचवर्शीय योजना का योजना परिव्यय 19.41 करोड़ रूपये है। इस में से 12.67 करोड़ रूपये ग्राम्य जल–सप्लाई स्कीमों के लिए और 6.74 करोड़ रूपये भाहरी जल–सप्लाई तथा मल–निकास स्कीमों के लिये रखे गये है। पांचवी योजनावधि के दौरान इस उपबन्ध से लगभग 621 गांवों में जल–सप्लाई, 5 नगरों में आंि ाक जल सप्लाई और 8 नगरों में छिटपुट मल–निकास की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है।

मार्च, 1976 के अन्त तक 859 गांवो में जल–सप्लाई सुविधावं प्रदान की गई जिन में 824 गांव जल की कमी वाले क्षेत्र में थे। चालू वित्त वर्श के दौरान 1.37 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 65 गांवों में यह सुविधा प्रदान की पाने की सम्भावना है। मार्च, 1976 के अन्त तक राज्य के 64 नगरों में आंि ाक जल–सप्लाई और 26 नगरों में छिप–पुट मल–निकास सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। चालू वित्त वर्श के अन्त तक राज्य के 66 नगरों में आर्थिक जल–सप्लाई और 28 नगरों में छिटपुट मल–निकास व्यवस्था कर दी जायेगी।

वित्त वर्श 1977–78 के दौरान इन योजनाओं के लिए 3.43 करोड़ रूपयों के अन्तिम परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस रा ि ा में से 2.45 करोड़ देहाती जल सप्लाई योजनाओं पर और 0.98 करोड़ रूपये भाहरी जल सप्लाई और मल निकास योजनाओं पर खर्च किये जाने प्रस्तावित है। इस रा ि ा से 115 अन्य गांवों में पीने के जल की सप्लाई, एक नगर में आंि ाक रूप से जल सप्लाई और दो नगरों में छिटपुट मल–निकास सुविधाएं लागू होगी।

गृह निर्माण

माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि जनसंख्या में वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप समृद्धि के कारण आवास समस्या गम्भीर होती जा रही है। इसके

परिणामस्वरूप मकानों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगस्त 1971 में हरियाणा गृह–निर्माण बोर्ड की स्थापना मकानों की कमी को दूर करने के उद्दे य से की गई थी। गृह–निर्माण बोर्ड मार्च, 1976 के अन्त तक 29000 और मकानों का निर्माण पूरा कर सका है। और यह आ ा है कि बोर्ड चालू वित्त वर्श के अन्त तक 2000 और मकानों का निर्माण पूरा कर सकेगा। यह भी आ ा है कि अगले वित्त वर्श के दौरान अर्थात् वर्श 1977–78 में बोर्ड 2000 अतिरिक्त मकानों का निर्माण कर सकेगा।

गुजरात और महाराश्ट्र राज्यों के अनुसार हरियाणा में भी सहकारी गृह–निर्माण अभियान चालू किया जा रहा है। एक ि ाखर गृह–निर्माण समिति स्थापित की गई है जिसकी प्राधिकृत पूंजी 5.00 करोड़ रूपये होगी। इस प्राधिकृत पूंजी में 20 प्रति ात हिस्से सरकार के होगें।

1974–75 से गृह–निर्माण विभाग की योजना में सरकारी रिहाय ाी भवनों के निर्माण का कार्यक्रम भी भाामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन पिछले दो वर्शो के दौरान 43.12 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की गई है और चालू वर्श के दौरान 38.74 लाख रूपये खर्च किए जाने की सम्भावना है। इस प्रयोजन के लिए वर्श 1977–78 के दौरान 54 लाख रूपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

सरकार अपने कर्मचारियों के लिए आवास की कमी की समस्या से भी परिचित है। अत्यधिक खर्च अैर सीमित वित्तीय साधन होने के कारण राज्य सरकार के लिए अपने सभी कर्मचारियों को आवास प्रदान करना सम्भव नहीं है। इसलिए सरकार कर्मचारियों को अपने गृह–निर्माण के लिए प्रोत्साहन देती रही है। इस प्रयोजन के लिए उन्हें गृह–निर्माण ऋण प्रदान किये जाते है। इस ऋण की अधिकतम सीमा 99000 रूपये है। चालू पंचवर्शीय योजना के पहले दो वशोंर् के दौरान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 1.44 करोड़ रूपये के गृह–निर्माण ऋण दिए गए है। गृह–निर्माण ऋणों के लिए चालू वर्श में 0.85 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया है। जबकि वित्त वर्श 1977–78 में 0.98 करोड़ रूपयों की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्ध देहाती भूमिहीन कामगारों को घरों के लिए पहले से ही अलॉट की गई जमीनों पर मकान बनाने के जोरदार कार्यक्रम को चालू करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए अलाटियों को अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रत्येक मकान की लागत का 80 प्रति ात ऋण के रूप में दिया जायेगा जिसकी वसूली आसान किस्तों में की जाएगी। मकान की लागत लगभग 3500 से 3700 रूपये है। इसमें 2400 से 3000 रूपये तक ऋण के रूप में दिये जाते है। बैंकों द्वारा यह ऋण सीधें ही ऋण लेने वाले व्यक्ति को कम ब्याज पर दिया जायेगा।

यह आ ाा की जाती है कि 31 मार्च, 1977 तक 25000 मकानों का निर्माण हो जाएगा और सम्पूर्ण परियोजना को पूरा होने में 5 वर्श लगेगें। इसी प्रकार भाहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे लोगों के लिए जिन के पास मकान की जमीन बने हुए मकान नहीं हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी नगर पालिका क्षेत्रों में प्रति मकान 5000 रूपये की लागत तक के बने हुये मकानों की व्यवस्था का निर्णय किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र समितियों के अन्तर्गत आने वाले भाहरी क्षेत्रों में रहने वाले इन व्यक्तियों के लिए प्रत्येक बेघर व्यक्ति को 50 वर्ग गज का प्लाट देने का प्रस्ताव है जिसकी लागत पांच बराबर किस्तों में वसूल की जायेगी। आ ाा की जाती है कि वर्श 1977–78 के दौरान ये सभी योजनाएं आगे बढ़ेगी।

रोजगार तथा श्रम कल्याण

वर्श 1975–76 के दौरान संगठित अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में रोजगार में अखिल भारतीय 2.3 प्रति ात के मुकाबले राज्य में 7.7 प्रति ात की वृद्धि हुई है। जनवरी से जून, 1976 तक 5537 अनुसूचित जाति के आवेदकों को तथा 2016 भूवपूर्व सैनिकों को सिविल नौकरियां दी गई । चालू वर्श के दौरान 309 अंधे, बहरे और गूंगे तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार दिये गये। चूंकि सभी आवेदकों को नौकरियां दिया जाना सम्भव नहीं हैख इसलिए विभाग ने स्वतः रोजगार की स्कीम चलाई है। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी से दिसम्बर, 1976 तक 5847

व्यक्तियों ने अपना–अपना रोजगार चालू किया । विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए 7.50 लाख रूपये की रा ि ा का उपबन्ध किया गया है।

राज्य में मजदूरों के कल्याण से सम्बन्ध अनेक कार्य किये गये है। पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या 1975 में 2180 थी जो बढ़ कर वर्श 1976 के दौरान 2370 हो गई। इस समय राज्य में आठ श्रम कल्याण केन्द्र है, जिन में कागारों तथा उनके आश्रितों को सिलाई, बुनाई, कढाई तथा संगीत इत्यादि में प्र ि ाक्षण दिया जाता है। महिला कामगारों के लााि के लिए तथा उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में उनका मार्गद र्ान करने के लिए एक महिला–कल्याण अधिकारी नियुक्त की गई है। नौकरी करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए फरीदाबाद तथा सोनीपत में ि ा ाु–गृह खोले गए है। कृशि के क्षेत्र में भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के वि ोश प्रयत्न किए जा रहे है।

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य कमजोर वगों का कल्याण

अनुसूचित जातियों, पिछड़ें वर्गों तथा विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है तथा कार्यान्वित भी की है। चौथी पंचवर्शीय योजना के दौरान छात्रवृवियां देने, ि ाक्षण भाुल्क की प्रतिपूर्ति, कृशि–भूमि खरीदने के लिए ऋण, औद्योगिक संस्थाओं/स्कूलों में प्र ि ाक्षण के लिए

वजीफे–घरों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता, पेयजल कुओं की व्यवस्था तथा चौपाल, निर्माण के लिए आर्थिक सहायता आदि विभिन्न कल्याण कार्यों पर 1.56 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे। अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सामुदायिक जीवन के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से चौथी पंचवर्शीय योजना के 1.56 करोड़ रूपये के कुल योजना परिव्यय में से 1000 चौपालों के निर्माण पर 26.35 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की गई।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लाभ हेतू विभिन्न विकास स्कीमों पर चौथी पंचवर्शीय योजना के दौरान 1.56 करोड़ रूपये खर्च करने के अतिरिक्त सरकार ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए इन समुदायों के पात्र व्यक्तियों को 1.26 करोड़ रूपये के ब्याज रहित ऋण दि तथा हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की हिस्सा पूंजी में भी प्र्याप्त रा ि ा दी। पांचवीं पंचवर्शीय योजना में अनुसूचित जातियो, पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य कममजोर वर्गों के कल्याण हेतु 1.70 करोड़ रूपये खर्च किये जाने की व्यवस्था है। चालू वित्त वर्श के अन्त तक विभिन्न कल्याण स्कीमों पर 0.87 करोड़ रूपयें की रा ि ा खर्च किये जाने की सम्भावना है। वर्श 1977–78 की योजना अवधि के लिए 0.42 करोड़ रूपये रखे गए है, इसमें से 14 लाख रूपये गृह निर्माण के लिए निर्धारित किए गये है। इस स्कीम के अधीन प्रति लाभानुभोगी को 2000 रूपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्श से ''प्राइमरी और मिडल कक्षाओं में पढ़ रही

हरिजन छात्राओं को वर्दियों की सप्लाई'' नामक एक नई स्कीम भाुरू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक छात्रा को 15 रूपये के मूल्य की निः ाुल्क वर्दी दी जायेगी।

समाज के इस वर्ग के लिए योजनेत्तर पक्ष की विभिन्न भौक्षणिक, आर्थिक और अन्य सामाजिक उत्थान स्कीमों पर 1977–78 में 89.20 लाख रूपये की रा ि ा खर्च करने का भी प्रस्ताव है।

सरकार के प्रयत्नों में बढ़ावा करने के लिए 2 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी से हरियाणा हरिजन कल्याण निगम जनवरी, 1971 से कार्य कर रहा हैं यह निगम हरिजनों को कर्जे और अन्य लाभ देता है जिससे कि वे विभिन्न व्यवसायों और अद्यागों को जैसे डेरीफार्मिंग, चमड़ा–उद्योग, भेड़ बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और हथ–करघा आदि को चलाने में समर्थ हो सके है। निगम, करनाल में पहले ही एक जुता केन्द्र स्थापित कर चुका है और हरिजनों के कल्याण के लिए अन्य लघु यूनिट स्थापित कर रही है।

समाज कल्याण सेवाएं

कई कार्यकम और नीतियां वि ाशतः समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए बनाई गई है, जिनमे निराश्रित महिलाएं, उन पर आश्रित बच्चे, वृह्ध और अ ाक्त, भाारीरिक तौर पर विकलांग, भिखारी और इसी प्रकार के समाज के अन्य जरूरतमंद

वर्ग भाामिल है। जहां वर्श 1966–67 में इस प्रकार के कार्यों के लिए केवल 10 लाख रूपये की रा ि ा उपबन्धित की गई थी । वर्श 1977–78 के लिए 87.15 लाख रूपये उपबन्धित किये गये है। पांचवी पंचवर्शीय योजना में विकलांग व्यक्तियों की ि ाक्षा और उनके कल्याण , परिवार एवं ि ा ु कल्याण, निर्धनों तथा निराश्रितों के कल्याण ओर सुधार गृहों के लिए 28.37 लाख रूपये का उपबन्ध किया गया है। 1977–78 की वार्शिक योजना के लिए 5 लाख रूपये की रा ि ा आवंटित की जा चुकी है तथा न्युनतम आव यकता कार्यक्रम के अधीन समाकलित ि ा ु विकास सेवाओं के अन्तर्गत पूरक–पोशण के लिए 8 लाख रूपये की और रा ि ा का उपबन्ध किया गया है। हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 के अधीन एकवि ोश सकूल तथा ि ा ु कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है। छछरौली के बाल गृह को उक्त अधिनियम के अधीन बाल गृह तथा अवलोकन गृह के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। भाहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चों में कुपोशण की समस्या को कम करने के लिए 13 नगरों में एक वि ोश पोशण कार्यक्रम भाुरू किया गया है ओर इस स्कीम के अधीन इस समय 16050 बच्चे और गर्भवती/पोशक महिलाएं लाभ उठा रही है। राज्य से भिक्षावृति की सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए पानीपत में भिखारियों के लिए एक प्रमाणित संस्था स्थापित की गई है। युवा निराश्रित महिलाओं और विधवाओं तथा उनके आश्रितों के लिए तीन आश्रय गृह चालू किये गये है और निराश्रित बच्चों के लिए कल्याण सेवाओं के उद्दे य से एक कार्यक्रम भाुरू

किया गया है ताकि वे समाज में सामान्य नागरिक के रूप में रह सकें।

आजीविका के साधनहीन, वृह्ध और निराश्रित व्यक्तियों की सामामजिक सुरक्षा के लिए वर्श 1969 में वृद्धावस्था, पैं ान स्कीम दोबारा भाुरू की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 7005 निराश्रित व्यक्ति पैं ान ले रहे है तथा इस स्कीम के अर्न्तगत 8000 पैं ान प्राप्त व्यक्तियों को आगामी वित्त वर्श में पैं ान देने के लिए उचित उपबन्ध किया गया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने अब वृद्धावस्था पैं ान की दर 25 रूपये मासिक से बढ़ाकर 50 रूपये मासिक कर देने का निर्णय लिया है (थंम्पिग)। जिला अम्बाला में साकेत के स्थान पर विकलांग बच्चों के लिए चिकित्सा भाासत्र तथा अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। पानीपत तथा सोनीपत में सरकार द्वारा अन्धों के लिए माध्यमिक स्तर तक ि ाक्षा की व्यवस्था तथावयस्क अन्धों के लिए व्यावसायिक प्र ि ाक्षण देने वाली दो आवासी संस्थाएं चलाई जा रही हैं गुड़गांव मैं बहरों तथा गूंगो को ि ाक्षा तथा प्र ि ाक्षण देने के लिए एक संस्था स्थापित की गई है। उच्च ि ाक्षा प्राप्ति के लिए छात्रवृति योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति 40 रूपये मासिक से 75 रूपये मासिक तक छात्रवृति देकर भाारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सहायता की जा रही हैं

विकलांग व्यक्तियों अर्थात् अन्धे, बहरे और गूंगों तथा 21 से 55 वर्श की आयु के विकलांग व्यक्तियों, जिनके

जीवनोंपार्जन का कोई साधन नहीं है और जो अपनी आजीविका कमा नहीं सकते, के लिए 1 अप्रैल 1977 से 50 रूपये प्रतिमास की दर से पैं ान देने की स्कीम बनाई गई है।

मैंने अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुक्ष क्षेत्रों का संक्षिप्त रूप से वर्णन करने का प्रयत्न किया है जिनमें राज्य तीव्र प्रगति कर रहा है, किन्तु यह एक पूर्ण विवरण नहीं है और मैं माननीय सदस्यों को इस तथ्य के विशय में सूचित करना चाहता हूं कि बहुत विभागीय गतिविधियों की चर्चा इस वि लेशण के अन्तर्गत नहीं की गई। भिन्न–भिन्न विभागों, जैसे सिविल विमानन विभाग, विकास तथा पंचायत, राजस्व, खाद्य तथा पूर्ति, औद्योगिक प्र ि ाक्षण, तकनीकी ि ाक्षा तथा पुरातत्व विभागों में विकास कार्य पर्याप्त रूप से चल रहा है। सिविल विमानन विभाग फसलों पर हवाई छिड़काव तथा राज्य में विभिन्न स्थानों पर हवाई अड्डों के निर्माण की स्कीम को सफलतापूर्वक कियान्वित कर रहा हैं इसके विभिन्न क्लबों में उड़ान तथा स्लाइडिंग प्र ि ाक्षण देने का भी प्रबन्ध किया गया है। विकास तथा पंचायत विभाग द्वारा हाल ही में पंचायत भवनों के निर्माण का कार्यकम आरम्भ किया गया है।

20 सूत्री कार्यकम के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्कीमों को जोरदार तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा अधिका ं लोगों ने इन नये उपायों से पर्याप्त लाभ उठाया है। इस काय्रकम से प्रगति के एक नये युग का सूत्रपात हुआ । इसके अन्तर्गत

आरम्भ किये गये प्र ाक्षुता कार्यक्रम से 4150 प्र ाक्षुओं को काम पर लगाने में सफलता मिली। मूल्य वृद्धि पर प्रभाव ाली रूप से नियन्त्रण रखा गया । 429 उचित मूल्य की दूकानें खोलकर आव यक वस्तुओं का वितरण किया गया। नियन्त्रित मुल्य के कपड़े का वितरण परचून की दुकानों के माध्यम से किया गया और राज्य में कोयले तथा सीमेंन्ट की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ। भूमि सुधार उपायों की गति तेज कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप राहत मिली तथा फालतू भूमि का वितरण किया गया। कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त सांस्थानिक ऋण सुनि चत किया गया। विद्यार्थियों को सस्ते दामों पर पुस्तकें तथा लेखन–सामग्री मुहैया करने के लिए बुक बैंकों की स्थापना की गई। हथकरघा उद्योग का अधिक विस्तार किया गया।

बजट में घाटा

मैं बजट दस्तावेजों में वित्तीय स्थिति पर आदरणीय सदस्यों का ध्यान पुनः आकर्शित करना चाहता हूं। वर्श 1977–78 के अन्त में राज्य बजट में घाटे का अनुमान 17.10 करोड़ रूपये है, जिस में वर्श 1976–77 के सं ाोधित अनुमानों के 5.58 करोड़ रूपये का घाटा भी भाामिल किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 1977 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की दो किस्तें देने के निर्णय से बजट का घाटा और बढ़ेगा। पूर्ण वित्तीय वर्श में इस से राज्य के कोश पर लगभग 3 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा।

सतलूज–यमुना योजक परियोजना के परिव्यय में कमी करने के कारण बजट घाटा कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि पंजाब के क्षेत्रों में इस परियोजना की कियान्विति में गति नहीं आ पाई है। मैं माननीय सदस्यों को वि वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस परियोजना को परिहार्य देरी के बिना नि चित रूप से पूरा करने के लिए प्रबल प्रयत्न करेगी।

आ ाा की जाती है कि इस घाटे को केन्द्रीय करों के राज्य सरकार को सम्भाव्य अतिरिक्त अन्तरण से तथा भारत सरकार की ओर से प्राप्त योजना सहायता जिसे चालू वित्त वर्श में 27.00 करोड़ रूपये की केन्दीय सहायता के वचन के मुकाबले वर्श 1977–78 के बजट अनुमानों में 11.40 करोड़ रूपये मान लिया गय है, कम किया जा सकेगा। प्र ाासनिक व्यय पर पूर्ण कड़ा नियन्त्रण रखने के लिए सतत प्रयत्न जारी रखे जाऐंगें। वर्श 1977–78 के बजट अनुमान इस परिकल्पना पर आधारित है कि कीमतों का वर्तमान स्तर बना रहेगा तथा कृशि औद्योगिक उत्पादन वर्तमान उत्पादन के स्तर से नीचे नहीं गिरेगा। वित्त वर्श 1977–78 में राजय में कृशि तथा औद्योगिक उत्पादन में और भी वृद्धि होने की सम्भावना है और हम राज्य के रास्वों में भी अधिक वृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगें। अतः हम वर्श 1977–78 के दौरान राज्य के साधनों का मध्यवधि पुनर्विलोकन करना चाहते है।

राज्य के साधनों पर पडे भार को कम करने के लिए एक अन्य क्षेत्र, जिस पर हम ध्यान दे रहें है, वह राज्य में विकास

सम्बन्धी गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने के लिए सांस्थानिक वित्त का अधिकतम प्रयोग हैं इस उद्दे य के लिए, हम ने पहले ही एक अलग सांस्थानिक वित्त विभाग की स्थापना की है। इस विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्य में अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक भाखाएं खोली गई तथा वि ोश्तया प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक उधार दिया गया। ग्रामीण आवास स्कीम के लिए वाणिज्यिक बैंकों की पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त कर ली गई है जिसके अधीन उन निर्धन ग्रामीणों को, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मकानों के लिए स्थान अलाट किये गये थे, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण दिये जा रहे है। इस स्कीम के अधीन बैंको ने लाभानुभोगियों को छेरी, मुर्गीपालन, सुअर पालन, भेड़ प्रजनन इत्यादि जैसे अनुशंगी व्यवसायों को आरम्भ करने के लिए उन्हे उत्पादक ऋण देने की भी व्यवस्था की है। इस स्कीम के प्रथम चरण में 25000 मकानों के निर्माण हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 10. 00 करोड रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की सम्भावना हैं।

ग्रामीण गरीबों की परम्परागत साहूकारों पर निर्भरता को कम करने के उद्दे य से , राज्य में ऋण देने की व्यवस्था को तीव्र किया गया है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत है कि इस समय राज्य में भिवानी तथा गुड़गांव में दो प्रादे ि ाक बैंक काम कर रहे हैं सीमान्त किसानों, कृशि श्रमिकों तथा ग्रामीण

कामगारों की जरूरतों को पूरा करने वाले बैंकों का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा रहा हैं।

इस प्रयोजन के लिए गठित टास्क फोस की सिफारि ाों पर भारत सरकार ने लेखा को लेखा परीक्षा से अलग करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ पराम र्ा कर के पृथक करने की स्कीम बना रही है और इसे 1977–78 के दौरान कार्यान्वित किये जाने की स्म्भावना है। लेखों को लेखा परीक्षा से अलग कर देने के प चात लेखे राज्य लेखा निदे ाालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा रखें जायेगें। इस पुनर्गठन से लेखों के संधारण में पर्याप्त सुधार होने की सम्भावना है। इस स्कीम के लिए बजट अनुमान 1977–78 में लगभग 0.85 करोड़ रूपये के अतिरिक्त खर्च का उपबन्ध किया गया है। इस खर्च के लिए राज्य सरकार को वित्तिय सहायता देने के बारे में हमने भारत सरकार के साथ मामला उठाया हैं।

आभार प्रद र्ान

अन्त में, मैं बजट तैयार करने में वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किये गये अथक परिश्रम के लिए उन के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके कारण मैं नियत तिथि पर सदन में बजट प्रस्तुत कर सका हूं। मैं महालेखाकार हरियाणा द्वारा दिये गये अमूल्य सहयोग के लिए उनका भी आभारी

हूं। मैं बजट दस्तावेज मुद्रित करने में चण्डीगढ़ प्र ाासन द्वारा दिये गये सहयोग के लियें उन के प्रति कृतज्ञ है।

महोदय, अब मैं वर्श 1977–78 के बजट अनुमानों की प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं।

जय हिंद (थंम्पिग)

Mr. Speaker: The House stands adjournded till 2.00 p.m. today.

11.41 A.M.

(The Sabha then Adjourned till 2.00 p.m. today (Thursday) the 24th March, 1977.